



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 249]

No. 249]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 15, 2003/आश्विन 23, 1925

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 15, 2003/ASVINA 23, 1925

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2003

प्रारंभिक जांच परिणाम

विषय :—जापान से मेटालर्जिकल कोक के आयातों से संबंधित पाटनरोधी शुल्क।
सं. 14/41/2002-डीजीएडी.—1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और उसकी सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आंकलन एवं वसूली और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के अंतर्गत:-

क. प्रक्रिया

1. जांच के संबध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:-
 - (i) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात् प्राधिकारी भी कहा गया है) को उपरोक्त नियमों के अंतर्गत घरेलू उद्योग की ओर से इंडियन मेटालर्जिकल कोक मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन (डमकोमा) (जिसे एतदपश्चात् याचिकाकर्ता कहा गया है) से लिखित आवेदन प्राप्त हुआ था जिसमें जापान मूल के अथवा वहां से निर्यातित मेटालर्जिकल कोक मैटाकॉक जिसे एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाया गया था। (मेटालर्जिकल कोक के निम्नलिखित घरेलू उत्पादक इस याचिका के पक्षकार हैं :-

मैसर्स बीएलए इंडस्ट्रीज लि०, मुम्बई

मैसर्स दुर्गापुर प्रोजेक्ट लि०, कोलकाता

(1)

मैसर्स अंतय बालाजी कोक लि०, कोलकाता

मैसर्स सौराष्ट्र फ्यूल्स प्रा० लि०, मुम्बई

मैसर्स सदरन फ्यूल्स लि०, बंगलौर

मैसर्स सेसा केम्बला कोक कं० लि०

- (ii) इस याचिका का समर्थन मैसर्स गुजरात एनआरई कोक लि०, कोलकाता द्वारा भी किया गया है।
- (iii) याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रारंभिक जांच में कतिपय कमियां प्रकट हुई थी जिन्हें बाद में याचिकाकर्ता द्वारा ठीक कर दिया गया था। अतः याचिका को विधिवत प्रलेखित माना गया था।
- (iv) प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर जापान से संबद्ध वस्तु के आयातों के खिलाफ जांच शुरू करने का निर्णय लिया। प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमों के उप-नियम 5(5) के अनुसार जांच की कार्रवाई शुरू करने से पहले पाटन के आरोप की प्राप्ति के विषय में नई दिल्ली में जापान दूतावास को सूचित किया।
- (v) प्राधिकारी ने 20 मार्च, 2003 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसे भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किया गया था जिसके द्वारा जापान (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध देश कहा गया है) के मूल अथवा वहां से निर्यातित मैटालर्जिकल कोक के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच शुरू की गयी थी जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची-1 के सीमाशुल्क कोड 27.04 और आईटीसी, एचएस वर्गीकरण नियम 2704.00 के अंतर्गत वर्गीकृत है।
- (vi) प्राधिकारी ने सार्वजनिक सूचना की प्रति सभी ज्ञात निर्यातकों (जिनका ब्यौरा याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध करवाया गया था) को भेजी और उपर्युक्त नियम 6(2) के अनुसार उन्हें पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर लिखित रूप में अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया।
- (vii) प्राधिकारी ने नियम 6(4) के अनुसार अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावली भेजी:-
 1. मैसर्स मित्सुबिसी कारपोरेशन, टोक्यो, जापान
 2. मैसर्स सुमितोमो कारपोरेशन, टोक्यो, जापान
- (viii) प्राधिकारी ने सार्वजनिक सूचना की प्रति भारत में संबद्ध वस्तु के सभी ज्ञात आयातकों (जिनका ब्यौरा याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध करवाया गया था) को भेजी और उन्हें नियम 6(2) के अनुसार

पत्र जारी होने की तारीख से चालीस दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने की सलाह दी ।

- (ix) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी) से भी अनुरोध किया गया कि वह जांच की अवधि सहित पिछले 3 वर्षों के दौरान भारत में किए गए संबद्ध वस्तु के आयातों के ब्यौरे प्रस्तुत करें ।
- (x) नई दिल्ली में संबद्ध देश के दूतावास को नियम 6(2) के अनुसार जांच की शुरुआत के बारे में सूचना दी गई और उनसे यह अनुरोध किया गया कि वे अपने देश के सभी संबंधित निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावली का जवाब निर्धारित समय के भीतर देने की सलाह दें । नियम 6(3) के अनुसार संबद्ध देश के दूतावास को ज्ञात निर्यातक को भेजे गए पत्र, याचिका तथा प्रश्नावली की एक प्रति भी भेजी गई थी । जहां अनुरोध किया गया वहां अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी अगोपनीय याचिका की एक प्रति प्रदान की गयी थी ।
- (xi) नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध माल के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ता एसोसिएशनों को एक प्रश्नावली आवश्यक सूचना के लिए भेजी गयी थी:-

- i) मैसर्स गुजरात हेवी कैमिकल्स लि०, अहमदाबाद, गुजरात
- ii) मैसर्स जायसवाल नेको लि०, कोलकाता
- iii) मैसर्स सदरन आयरन एण्ड स्टील कं०, कोयम्बटूर, तमिलनाडु
- iv) मैसर्स सतवाहन इस्पात लि०, हैदराबाद
- v) मैसर्स किलोस्कर फेरस इन्डस्ट्रीज, पुणे
- vi) मैसर्स यूनिमैटल इस्पात लि०, सिकंदराबाद
- vii) मैसर्स मात्विका स्टील लि०, सुल्तानपुर
- viii) मैसर्स लांको इंडस्ट्रीज लि०, सिकंदराबाद
- ix) मैसर्स टिस्को लि०, मुम्बई
- x) मैसर्स विश्वेसरैया आयरन एण्ड स्टील, भद्रावती, कर्नाटक
- xi) मैसर्स यूनिमैटल एल्लॉयज लि०, सिकंदराबाद

- xii) मैसर्स गुजरात हेवी कैमिकल्स, अहमदाबाद, गुजरात
- xiii) मैसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडियन मिनी ब्लास्ट फर्नेसेस, नई दिल्ली
- xiv) मैसर्स इंडियन फ़ैरो एल्लॉय प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, मुम्बई

(xii) कुछेक पक्षकारों ने जांच आरंभ करने संबंधी अधिसूचना का अपना उत्तर प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा बढ़ाए जाने का अनुरोध किया था। तदनुसार, सभी हितबद्ध पक्षकारों के लिए समय की सीमा 15 मई, 2003 तक बढ़ायी गयी थी।

(xiii) निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा प्रश्नावली/अधिसूचना का उत्तर प्रस्तुत किया गया था:-

1. मैसर्स मित्सुबिसी कारपोरेशन, जापान
2. मैसर्स जेएफई स्टील कारपोरेशन, जापान

मैसर्स सुमितोमो कारपोरेशन, टोक्यो, जापान जिसका याचिका में मूल नाम दिया गया है, ने भी जांच आरंभ करने संबंधी नोटिस का उत्तर दिया है और यह सूचित किया है कि उन्होंने 1 अप्रैल, 2001 से जून, 2002 के दौरान जापान से भारत को किसी मैटकोक का निर्यात नहीं किया था। तथापि, मैसर्स जेएफई स्टील कारपोरेशन, जापान जो संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का वास्तविक उत्पादक है, ने स्वतः उत्तर दिया है और इस जांच में सहयोग देने पर सहमत हुआ है। जापान में मैटकोक के दो प्रमुख उत्पादक अर्थात् मैसर्स एनकेके कारपोरेशन और मैसर्स कावासाकी स्टील का 1 अप्रैल, 2003 से एक नए कारपोरेशन के रूप में विलय हो गया है जिसका नाम मैसर्स जेएफई स्टील कारपोरेशन है।

(xiv) निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ता एसोसिएशनों द्वारा प्रश्नावली/अधिसूचना का उत्तर दिया गया है:-

1. मैसर्स इंडियन फ़ैरो एल्लॉयज प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, कोलकाता
2. मैसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडियन मिनी-ब्लास्ट फर्नेसेस
3. मैसर्स इलैक्ट्रोस्टील कास्टिंग्स लि०
4. मैसर्स अपरेंट आयरन एण्ड स्टील प्रा० लि०
5. मैसर्स हिन्दुस्तान जिक लि०
6. मैसर्स सौराष्ट्र कैमिकल्स लि०

7. मैसर्स फेयर डील सप्लायर्स प्रा० लि०
8. मैसर्स जायसवाल नेको लि०
9. मैसर्स ऊषा बेल्ट्रॉन लि०
10. मैसर्स इस्पात मेटालिक्स इंडिया लि०
11. मैसर्स टिस्को
12. मैसर्स कल्याणी फेरस इंडिया लि०
13. मैसर्स किलोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज लि०
14. मैसर्स ऊषा इस्पात लि०

(xv) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय अंशों को इस प्रयोजनार्थ बनाई गई एक सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराया और इसे हितबद्ध पार्टियों द्वारा जांच के लिए खुला रखा ।

(xvi) प्राधिकारी ने याचिकाकर्ताओं के परिसर में संभव सीमा तक मौके पर जांच की सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) और याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर उत्पादन की ईष्टतम लागत और भारत में सम्बद्ध वस्तु को बनाने और बेचने की लागत परिकलित करने के लिए लागत जांच भी की गई ।

(xvii) विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर प्राधिकारी ने पक्षकारों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों को समझने के लिए एक सार्वजनिक सुनवाई की और सुनवाई के पश्चात किए गए लिखित अनुरोधों और उनके उत्तरों को इस जांच परिणाम में शामिल किया गया है ।

xviii) *** यह चिन्ह इस अधिसूचना में किसी हितबद्ध पार्टी द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना तथा नियमों के अन्तर्गत प्राधिकारी द्वारा उसे ऐसा ही माने जाने का द्योतक है ।

xix) यह जांच 1 अप्रैल, 2001 से 30 जून, 2002 अर्थात् जांच की अवधि (पीओआई) के लिए की गई थी ।

ख. निर्यातक, आयातक और अन्य हितबद्ध पार्टियों के विचार

1. याचिकाकर्ता के विचार

(क) विचाराधीन उत्पाद

वह उत्पाद जिसके लिए यह याचिका दायर की गई जहाँ 18% से कम के ऐश तत्व वाला मटालर्जिकल कोक (मेट कोक) है जिसका जापान के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटन किया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि जापान से आयातित सम्बद्ध मेटकोक में 13% से कम के ऐश तत्व वाले कोकिंग कोयल का उपयोग होता है और इसलिए केवल 18% तक के सम्बद्ध मेटकोक का भारत में आयात किया जा रहा है।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि उच्च ऐश तत्व वाला कोयला मुख्यतया भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। जबकि आयातित सम्बद्ध मेटकोक का विनिर्माण कम ऐश तत्व वाले कोयले से किया जाता है और इसलिए यह ऐश तत्व में 18% से अधिक नहीं होगा। सम्बद्ध मेटकोक का उत्पादन कोयल को जलाए बिना सामान्यतः लगभग 1000 डिग्री सेन्टीग्रेट के उच्च तापमान पर आक्सीजन के बिना मेटलर्जिकल कोकिंग कोल के विखंडनात्मक आसवन द्वारा किया जाता है।

परिणामी सम्बद्ध मेटकोक की विशेषताएं प्रत्यक्ष रूप से कोयले की निविष्टि पर निर्भर करती हैं। 18% से कम के ऐश तत्व वाले किसी मेटकोक के लिए 13% से कम के प्राकृतिक ऐश तत्व वाली कोयला निविष्टि की आवश्यकता होगी जिसके लिए कोयले का आयात किया जाता है। भारतीय कोयले में आमतौर पर 20% से अधिक का प्राकृतिक ऐश तत्व होता है।

उत्पादित मेटकोक मुख्यतः कुछ खनिज और अवशिष्ट वाष्पशील सामग्री के साथ कार्बन है। मेटकोक का उपयोग ऐसे उद्योगों में प्राथमिक इन्धन के रूप में होता है जहाँ भट्टों और भट्टियों में एकसमान और उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। मेटकोक सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 27 (उप-शीर्ष 27.043 के अन्तर्गत) के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि यहाँ उल्लिखित वर्गीकरण

विनिर्माण प्रक्रिया और उत्पाद का उपयोग केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर किसी भी प्रकार बाध्यकारी नहीं है ।

मैटकोक (जिसमें सम्बद्ध मैटकोक शामिल हैं) का प्रयोग पिग आयरन, ढलाईखानों, लौह मिश्र धातुओं, रसायनों, सम्पूर्ण स्टील संयंत्रों और अन्य सहित विभिन्न उद्योगों में किया जाता है ।

जब यह बताया गया है कि विचाराधीन उत्पाद 18% से कम के ऐश तत्व वाला सम्बद्ध मैटकोक है, तब 18% से अधिक ऐश तत्व वाले सम्बद्ध मैटकोक के उत्पादनों को याचिकाकर्त्ताओं द्वारा उनकी याचिका से अलग कर दिया गया है ।

ख. समान उत्पाद

याचिकाकर्त्ताओं का दावा है कि आयातित उत्पाद और याचिकाकर्त्ताओं के उत्पादों में कोई दृष्टिकोण अन्तर नहीं है । भारत में याचिकाकर्त्ताओं द्वारा उत्पादित सम्बद्ध मैटकोक जापान से आयातित सम्बद्ध मैटकोक के साथ प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्थापनीय है ।

ग. भारतीय उद्योग-रूपरेखा

भारत में सम्बद्ध मैटकोक के उत्पादकों को मौटे तौर पर तीन समूहों में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है । पहले वे जिनके मुख्यतः समेकित स्टील संयंत्र हैं जैसे टिस्को, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड और सेल । ये स्वयं द्वारा उत्पादित सम्बद्ध मैटकोक की आबद्ध रूप से खपत करते हैं और साथ ही साथ जापान सहित अन्य देशों से बड़े पैमाने पर आयातों का सहारा लेते हैं । दूसरे अकेले सम्बद्ध मैटकोक के उत्पादक जो आयातित कम ऐश कोयले से सम्बद्ध मैटकोक का उत्पादन करते हैं, और तीसरे, बिहार, बंगाल और झारखंड में स्थित अकेले लघु उद्योग उत्पादक जिनका उद्योग और वाणिज्य संघों (आईसीए) द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है । परवर्ती सामान्यतः मैटकोक के उत्पादन के लिए भारतीय कोयले का उपयोग करते हैं और 18% से अधिक ऐश तत्व वाले मैटकोक के बड़े उत्पादक हैं ।

पूर्ववर्ती मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग का सीमांकन करने के उद्देश्य से चीन के मैटकोक को शामिल करते हुए उन उत्पादकों को निकाल दिया है जो विद्युत्-आधारित उत्पाद का आबद्ध रूप से उत्पादन और उपभोग कर रहे हैं। इस तथ्य की पुष्टि माननीय सीगेट द्वारा की गई थी। याचिकाकर्ताओं की जानकारी के अनुसार कोई भी उत्पादक 18% से कम ऐश तत्व वाले मैटकोक का उत्पादन आबद्ध खपत के लिए नहीं करता है। किसी भी स्थिति में इन आबद्ध उपभोक्ताओं को माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी और माननीय सीगेट के निर्णय को ध्यान में रखते हुए बाहर रखा जा सकता है।

घ. उत्पादन प्रक्रिया

कोक बनाने की प्रक्रियाओं में वाष्पशील पदार्थ (वीएम) वाले बिटुमिन्स कोयले को सामान्यतः आधारित सामग्री के आकार एवं गुणवत्ता के नियंत्रण हेतु प्रसंस्करण प्रक्रियाओं के पश्चात् श्रृंखलाबद्ध ओवनों में डाला जाता है जिन्हें सीलबंद करके आक्सीजन के अभाव में विशिष्ट रूप से कोयले एवं उसके वी.एम. तत्व की गुणवत्ता के अनुसार 14 से 36 घंटों के चक्रों में उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। मैटकोक के विनिर्माण की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप से दो प्रकार की होती हैं:-

नॉन रिकवरी प्रक्रिया

नॉन रिकवरी प्रक्रिया में वाष्पशील यौगिक जिन्हें गर्म करने के कारण कोयले से बाहर निकाल दिया जाता है, ओवन के भीतर पूरी तरह जल पाते हैं और ओवन में शेष रह जाने वाला ठोस कार्बन कोक है। इसे शमन टावर में ले जाया जाता है जहाँ इसे एक जल छिड़काव अथवा एक निष्क्रिय गैस (नाइट्रोजन) के प्रवाह, एक ऐसी प्रक्रिया जिसे शुष्क शमन के नाम से जाना जाता है, के द्वारा ठंडा किया जाता है। कोक को विभिन्न आकारों में छांटा जाता है और विस्फोट भट्टियों अथवा भंडारों में भेज दिया जाता है।

सह-उत्पाद रिकवरी प्रक्रिया

सह - उत्पाद रिकवरी प्रक्रिया में वाष्पशील पदार्थ को एकत्र किया जाता है। कोक ओवन गैस को ठंडा किया जाता है और सह-उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। कोक ओवन गैस को ठण्डा करने और प्रथमिक कूलर्स से प्राप्त द्रव्य से बनी सम्प्रवाहन द्रव में तारकोल होता है और इसे तारकोक निथरनी में डाल दिया

जाता है। कोक ओवन गैस से अधिक तारकोल निकालने के लिए स्थिर-विद्युतिकी अवक्षेपण हौज का उपयोग किया जाता है। फिर तारकोल को गोदाभों में भेज दिया जाता है। अमोनिया द्रव को भी तारकोल निथरनी से अलग किया जाता है और अमोनिया निकालने के पश्चात् अवशिष्ट जल अभिक्रिया में डाल दिया जाता है। कोक ओवन गैस को फिर से अन्तिम कूलर में ठंडा किया जाता है। अन्तिम कूलर में सैपरेटर से नेप्थेलिन अलग किया जाता है। फिर कोक ओवन गैस से हल्के तेल को अलग किया जाता है और बैन्जीन, टोल्यूईन और जिलीन प्राप्त करने के लिए इसके टुकड़े किए जाते हैं। कुछ सुविधाओं में एक ऑनसाइट तारकोल आसवन एकक शामिल हो सकती है। कोक ओवन गैस से सल्फर प्राप्त करने के लिए आमतौर पर क्लाडस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। कोक ओवन गैस का प्रयोग विद्युत संयंत्रों में और इसमें से हानिकारक तत्व निकालने के पश्चात् गर्म करने के लिए इंधन के रूप में भी प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। कोक ओवन गैस की रिकवरी वल्यू आमतौर पर इसकी कैलीरीफिक वैल्यू पर निर्भर करती है और रिकवरी की मात्रा क्यूबिक मीटर में मापी जाती है।

याचिकाकर्ता और उनके समर्थकों में से केवल मै० दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स ने रिकवरी प्रक्रिया का प्रयोग किया है। मै० दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लि० के वास्तविक अनुभव के आधार पर रिकवरी कोक के विनिर्माण की लागत का लगभग **% रही है।

याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया है और इस बात पर जोर दिया है कि एक रिकवरी कोक ओवर संयंत्र को स्थापित करने की पूंजीगत लागत गैर-रिकवरी संयंत्र की लागत से काफी अधिक है और इसलिए वास्तविक रिकवरी लाभ पूंजीगत लागत को ध्यान में रखते हुए काफी कम है।

कोक को ठंडा करने, उसकी हैंडलिंग और छंटाई प्रचालन के दौरान कोक ब्रीज का उत्पादन होता है। इसका या तो साइट पर पुनः उपयोग किया जाता है (अर्थात् सिन्टर संयंत्र में) अथवा साइट पर एक सह-उत्पाद के रूप में बेच दिया जाता है। यह दोनों प्रक्रियाओं के तहत होता है।

ड. मैटकोक के प्रयोक्ता

लोहा ढलाईखाने:- लोहा ढलाईखानों में कोक का प्रयोग क्यूपोला में किया जाता है ताकि लोहे को पिघलाकर उपयोगानुसार उसे भिन्न-भिन्न आकारों में ढाला जा सके ।

इस्पात ढलाईखाने:- इस्पात ढलाईखानों में कोक का उपयोग ढलाई के विनिर्देशन के अनुसार मोल्टन मैटल में अतिरिक्त कार्बन तत्व उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है ।

अलौह धातु की ढलाई:- तांबे और पीतल की ढलाई करने वाले ढलाई खानों द्वारा कोक का उपयोग धातु को पिघलाने के लिए किया जाता है ।

सीसा तथा जस्ता प्रगालक:- सीसा एवं जस्ते को गलाने की प्रक्रिया में कोक एक प्राथमिक संघटक होता है ।

इस्पात के गौण उत्पादक:- पुर्नचक्रिकृत स्टील स्क्रेप तथा स्पंज लोहे से इस्पात उत्पादन करने वाले "लघु" इस्पात संयंत्रों को कोक की जरूरत होती है ।

रसायन संयंत्र:- सोडा ऐश के कुछेक संयंत्रों तथा कैल्शियम कारबाइड के कुछ उत्पादकों को अपनी प्रक्रिया में कोक की जरूरत होती है ।

फैरो एलॉय संयंत्र:- फैरो एलॉय के उत्पादकों के लिए अपने उत्पादन हेतु कोक अपेक्षित होता है । इस प्रक्रिया में कोक का उपयोग अपचायक एजेंट के रूप में किया जाता है ।

ढलवाँ लोहे के उत्पादक:- ढलवाँ लोहे के उत्पादन में कोक की आवश्यकता पड़ती है । भारत में ढलवा लोहे के छोटे उत्पादकों को कोक की आवश्यकता होती हैं जिसे वे खुले बाजार से खरीदते हैं । विशिष्ट रूप से बड़े इस्पात उत्पादकों के पास अपने संयंत्र हैं और इसलिए इन्हें बाजार से कोक खरीदने की आवश्यकता नहीं है ।

(च) मैटकोक का आयात

संबद्ध मैटकोक का आयात 1999-2002

जापान		अन्य देश		योग
1999-2000	मात्रा मी.टन में	329472	1989931	2319403
	मूल्य रुपये में	1119654298	6793571892	7913236690
	दर रु./मी.टन	3398	3414	3412

2000-2001	मात्रा मी.टन में	200309	2184129	2384438
	मूल्य रुपये में	86190399	8187752510	9849655809
	दर रु./मी.टन	4303	4115	4131
2001-2002	मात्रा मी.टन में	371018	1912991	2284009
	मूल्य रुपये में	1494552853	7670211501	9170764354
	दर रु./मी.टन	4028	4013	4015

रूस और चीन को छोड़कर अन्य देशों से आयात निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम रहे हैं और इसलिए इसे भारत में पाटन नहीं माना जा रहा है। चीन से हुए आयात, जो कुल आयातों का लगभग 50.51% बनता है, पर वर्ष 1998 से पाटनरोधी शुल्क लगाया जा रहा है।

च. पाटन और सामान्य मूल्य

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र में कोयले की लागत के अलावा किसी अन्य उपयोगी सूचना के अभाव में वे निर्यातक देश के घरेलू बाजार में संबद्ध मेटकोक की बिक्री कीमत प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं। तदनुसार, उन्होंने आस्ट्रेलिया, चीन और कनाडा से जापान द्वारा आयातित कोयले की अंतर्राष्ट्रीय कीमत और समुचित संशोधनों के साथ रिकवरी तथा नान-रिकवरी प्रक्रियाओं का प्रयोग करने वाले भारतीय विनिर्माताओं की लागत के आधार पर संबद्ध मेटकोक का सामान्य मूल्य **** परिकलित किया है।

निर्यात कीमत संबंधी अनुमान

जापान से संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत की गणना डीजीसीआई एण्ड एस के आयात संबंधी आंकड़ों के आधार पर की गई है। चूंकि डीजीसीआई एण्ड एस के आंकड़े सीआईएफ आधार पर हैं, इसलिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय परिवहन प्रभारों, जापान में पत्तन प्रहस्तन प्रभारों, व्यापार गृह कमीशन के लिए समायोजन किए गए हैं।

किए गए उपर्युक्त समायोजनों के पश्चात याचिकाकर्ताओं द्वारा समायोजित कारखाना द्वार पर कीमत *** रूपए निकाली गई है।

उपर्युक्त परिकलित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर याचिकाकर्ताओं के रुपये एवं डालर दोनों के अनुसार पाटन मार्जिन 64.06% बताया है।

छ. क्षति

याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क दिया है कि संबद्ध देश से पाटन मार्जिन 2% की सीमा से अधिक है जिसे निर्यात कीमत के % रूप में व्यक्त किया गया है। संबद्ध देश से आयात की मात्रा भी निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग को पाटन के कारण वास्तविक क्षति हुई है जैसाकि नीचे बताए गए विभिन्न आर्थिक और वित्तीय मापदंडों से स्पष्ट होता है:-

- उद्योग को 1998 में चीन से संबद्ध मेटकोक के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद राहत मिली थी और उन्होंने क्षमता विस्तार की योजना बनाई थी। तथापि, जापान से पाटित आयातों के कारण उद्योग के समक्ष नई समस्याएं आ रही हैं।
- कुल आयातों की तुलना में संबद्ध देश से हुए आयात 2000-2001 में 8.40% से पर्याप्ततः बढ़कर जाँच अवधि के दौरान 22.62% हो गए हैं।

2 वर्ष	संबद्ध देश से आयात (मी.टन)	कुल आयात	% हिस्सा
1999-2000	329472.00	2319403.00	14.21%
2000-2001	200309.00	2384438.00	8.40%
पीओआई	660753.00	2921303.00	22.62%

स्रोत: डीजीसीआई एण्ड एस

- इसके अलावा, संबद्ध देश से हुए आयातों में देश में कुल मांग की तुलना में भी वृद्धि हुई है जो वर्ष 2000-2001 में 6.49% से बढ़कर जाँच अवधि के दौरान 20.28% हो गई है ।
- कि वर्ष 2000-2001 में 4303/-रुपए प्रति मी० टन की औसत कीमत की तुलना में जाँच अवधि के दौरान संबद्ध देश से 4188/-रुपए प्रति मी.टन की औसत कीमत पर आयात हुए हैं ।
- कि यद्यपि घरेलू उद्योग ने 1999-2000 की तुलना में जाँच अवधि के दौरान अपनी क्षमता में लगभग 328% तक की वृद्धि की है, तथापि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में हुई वृद्धि को देश में नई स्थापित क्षमता के संदर्भ में देखा जाना चाहिए । माँग भी 1999-2000 में 26, 88, 499 मी. टन से बढ़कर जाँच अवधि के दौरान 32,58,344 मी. टन हो गई है ।
- शिकायतकर्ता घरेलू उद्योग ने अपने ग्राहकों को बनाए रखने का भरपूर प्रयास किया है । फिर भी यह तथ्य कि जाँच अवधि के दौरान भारत में 6,60,753 मी. टन के पाटित आयात हुए हैं, इस बात का पर्याप्त साक्ष्य है कि इसने अपने संभावित ग्राहक गवाएं हैं ।
- यह देखा जा सकता है कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में जाँच अवधि के दौरान याचिकाकर्ताओं के उत्पादन में मात्रात्मक रूप से वृद्धि हुई । तथापि ऐसा आवश्यक रूप से घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि के कारण हुआ है । चीन से शुल्क के लागू होने के पश्चात घरेलू उद्योग की स्थिति में सुधार हो रहा था, तथापि, जापान से पाटन और तत्पश्चात चीन से पुनः पाटन आरंभ होने से इन प्रयासों को धक्का लगा है ।
- मात्रात्मक रूप से उत्पादन में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में जाँच अवधि के दौरान लगभग ***% तक की मामूली वृद्धि हुई है ।
- यद्यपि, याचिकाकर्ताओं द्वारा बिक्री की मात्रा में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में जाँच अवधि के दौरान वृद्धि की गई है तथापि, उद्योग को 1999-2000 की कीमत की तुलना में जाँच अवधि में कीमत प्राप्त नहीं हो रही है । संबद्ध देश से आयातों से कीमत पर पड़े दबाव के कारण घरेलू उद्योग उचित कीमत या आय की तर्कसंगत दर प्राप्त करने में अक्षम रहा है, जैसाकि नीचे दी गई तालिका से देखा जा सकता है :-

वर्ष	बिक्री मात्रा (मी.टन)	बिक्री मूल्य (लाख रु. में)	इकाई कीमत (रु०/मी०टन)
1999-2000	100.00*	100.00*	100.00*
2000-2001	213.81*	192.41*	89.99*
2001-2002	328.40*	313.59*	95.49*

* सूचीबद्ध आंकड़े

- भण्डार सूची:- याचिकाकर्ताओं की भण्डार सूची मार्च, 2001 के अंत में **** मी. टन से घटकर 31.3.2002 के अनुसार **** मी. टन रह गई है ।
- रोजगार:- घरेलू उद्योग की बढ़ी हुई क्षमता के कारण, रोजगार में वृद्धि हुई है । इस प्रकार घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में रोजगार के आधार पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है ।
- मजदूरी:- मजदूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि मजदूरी का निर्धारण श्रम कानूनों के अनुसार किया जाता है । मजदूरी में याचिकाकर्ता कम्पनियों की वित्तीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन नहीं किया जा सकता है ।
- लाभप्रदता:- अपने बाजार हिस्से को बनाए रखने के लिए घरेलू उद्योग के पास अपनी कीमतों को अलाभकारी स्तरों तक घटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था ।
- निवेश पर आय (लगाई गई पूंजी) : उपर्युक्तानुसार उद्योग घाटे में चल रहा है और इसलिए घरेलू उद्योग अपनी निविष्टियों पर कोई आय अर्जित करने में अक्षम रहा है ।
- कम कीमत पर बिक्री:- जापान से विचाराधीन उत्पाद को पहुँच मूल्य (4397 रूपए) उन कीमतों से काफी कम है जो घरेलू उद्योग को संबद्ध वस्तु की बिक्री पर प्राप्त होनी चाहिए थी । कम कीमत पर बिक्री के इस उच्च स्तर के क्षतिकारी प्रभाव का घरेलू उद्योग के वित्तीय-निष्पादन पर प्रत्यक्ष और घातक प्रभाव पड़ा है ।

		जापान
1.	घरेलू उद्योग की वांछनीय बिक्री कीमत (उत्पाद शुल्क को छोड़कर)	***
2.	आयातित उत्पाद का पहुँच मूल्य	4397
3.	कम कीमत पर बिक्री की मात्रा	***
4.	कम कीमत पर बिक्री का % (3/1)	***

31.03.2003 के आंकड़ों पर आधारित

- कीमत कटौती:- पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग पर क्षति के प्रभाव में इस तथ्य के कारण प्रबलता आई है कि न केवल संबद्ध वस्तु की बिक्री कम कीमत पर की जा रही है बल्कि संबद्ध देश के निर्यातक कीमत कटौती में भी लिप्त हैं। जाँच अवधि के दौरान पाटित आयातों का पहुँच मूल्य (अर्थात् सी.आई.एफ. कीमत योग सीमाशुल्क) घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से बहुत कम रहा है। अतः घरेलू उद्योग पर अपनी कीमतों को वर्तमान कीमतों जो कि बिल्कुल भी लाभप्रद नहीं हैं, से भी कम करने का लगातार दबाव है।
- कि घरेलू उद्योग लगाई गई पूँजी पर नाम मात्र की भी आय प्राप्त करने में अक्षम रहा है। अतः इस उद्योग में माल सूची के काफी अधिक स्तरों के साथ-साथ नकदी प्रवाह काफी प्रभावित हुआ है।
- कि उद्योग को नाममात्र की आय होने के कारण तथा पाटित आयातों के जारी रहने के कारण इस तथ्य के बावजूद कि वह घरेलू माँग के मात्र एक छोटे हिस्से को पूरा करता है, घरेलू उद्योग राष्ट्रीय हित में विकास करने की स्थिति में नहीं है।

ग. निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

1. निर्यातक के विचार:

i) जाँच अवधि

वर्तमान जाँच में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा मानी गई जाँच अवधि (पीओआई) का निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों द्वारा तथा भारत में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा और विश्व भर में अन्य जाँचकर्ता प्राधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया द्वारा भी समर्थन अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित आधारों पर नहीं किया गया है :-

(क) निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान है कि जाँच अवधि को यथा संभव हाल का होना चाहिए । इस मामले में परिगणन में ली गई अवधि जाँच प्रारंभ करते समय यथा संभव हाल की नहीं थी ।

(ख) अन्य मामलों में निर्धारित की गई जाँच अवधि इस मामले की तुलना में अधिक हाल की थी ।

(ग) वस्तुतः निर्दिष्ट प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को (अन्य मामलों में), जब यह पाया है कि याचिका की अवधि काफी पुरानी है और आँकड़े काफी पुराने हो सकते हैं, याचिका को अद्यतन करने का निर्देश दिया है ।

(घ) वर्तमान जाँच अवधि के समाप्त होने के पश्चात् मेट कोक की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है । इसी समय, उत्पादन लागत काफी हद तक उसी मात्रा में बनी रही है । यह कार्य मेट कोक बाजार के कार्यकलापों में भारी परिवर्तन होने के कारण हुआ है । याचिकाकर्ता ने जाँच शुरूआत करने से पूर्व निर्दिष्ट प्राधिकारी से चुपचाप इस तथ्य को बाद में जाँच की प्रक्रिया के दौरान संभवतः यह आरोप लगाने के लिए छुपाया है कि यह बदला हुआ परिदृश्य जाँच अवधि के बाद की घटना का है ।

(ङ.) आँकड़ों/सूचना की उपलब्धता निर्धारित अवधि का समर्थन नहीं करती है । जाँच शुरूआत की तारीख पर आयातों के संबंध में आँकड़े कम से कम अक्टूबर, 2002 तक के लिए उपलब्ध थे । इसके अतिरिक्त, ऐसा समझा जाता है कि ऐसे मामलों में, जब यह पाया जाता है कि याचिका की अवधि पुरानी है, निदेशालय में जाँच अवधि को याचिका में दी गई अवधि से तीन महीने आगे बढ़ाने की प्रक्रिया रही है ।

(च) प्रतिवादी निर्यातक यह समझते हैं कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने हाल ही में यह माना है कि पीओआई के बाद के अत्यावश्यक कारकों की उपेक्षा नहीं की जा सकती बशर्ते कि उनका पूरे मामले पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता हो। वर्तमान मामले में, कीमतों का 140-150 अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन (एफओबी) के स्तर तक बढ़ना, जब कि पीओआई में कीमतें 90-100 अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन तक थी, एक महत्वपूर्ण कारक है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती जबकि याचिकाकर्ता ने जानबूझकर एक बहुत पुराने पीओआई को चुना है। इस संबंध में यह नोट किया जाना चाहिए कि मेटकोक की कीमतों में वृद्धि वैश्विक तथा महत्वपूर्ण है। चीन में संयंत्रों को बंद किए जाने के कारण हुई कीमत वृद्धि अस्थायी नहीं है।

ii) घरेलू उद्योग की स्थिति:

प्रतिवादी निर्यातक दावा करते हैं कि स्थिति संबंधी अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया गया है चूँकि बिहार, बंगाल तथा झारखंड के आबद्ध उत्पादकों और लघु उत्पादकों (जिनका प्रतिनिधित्व उद्योग एवं वाणिज्य एसोसिएशन, आईसीए द्वारा किया जाता है) की उत्पादन क्षमता पर विचार नहीं किया गया है। वे तर्क देते हैं कि विभिन्न उत्पादकों द्वारा उत्पादन के संबंध में याचिका में बहुत सारी अटकलें हैं और कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस बात का याचिका में कोई साक्ष्य नहीं है कि आईसीए सदस्य 18% से अधिक ऐश तत्व वाले मेट कोक का उत्पादन करते हैं। वस्तुतः वे 18% से कम ऐश तत्व वाले मेट कोक का उत्पादन करते हैं। इसके अतिरिक्त, याचिका में कुछ पार्टियों द्वारा आयातों के बारे में कोई साक्ष्य नहीं है। याचिकाकर्ता ने चीन के मेट कोक और सीगेट निर्णय से संबंधित मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी के जाँच परिणाम का संदर्भ लेते हुए आबद्ध उत्पादकों को अलग कर दिया है। तथापि, संयुक्त राज्य : जापान से हॉट रोल्ड स्टील उत्पाद के मामले में डब्ल्यूटीओ के निर्णय के अनुसार मात्र इसलिए कि किसी कंपनी ने कैप्टिव प्रयोजनों के लिए वस्तु का उपभोग किया है, ऐसे उत्पादन को अलग नहीं किया जा सकता।

याचिकाकर्ता ने कुछ उत्पादकों द्वारा किए गए उत्पादन को मात्र इस आधार पर अलग कर दिया है कि वे मात्र आबद्ध प्रयोजनों के लिए उत्पादन करते हैं। तथापि, अन्य संगत नियमों के साथ पठित नियम 5(3) में आबद्ध उत्पादन तथा व्यापारिक उत्पादन के बीच कोई अंतर नहीं किया गया है। नियम 2(ख) की परिभाषा में संशोधन से स्वयं आयात करने वाले आयातक अथवा उत्पादक से संबंधित किसी उत्पादक का स्वतः अलगाव नहीं हो सकता। इस प्रकार अलग किए जाने के लिए पर्याप्त आधार होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, इस प्रकार अलग किए जाने का कार्य मात्र निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा किया जा सकता है, याचिकाकर्ता द्वारा नहीं।

iii) विचाराधीन उत्पाद

चीन के विरुद्ध जाँच में विचाराधीन उत्पाद 15% तक ऐश तत्व वाला मेट कोक था। वर्तमान याचिका में 18% तक ऐश तत्व वाले मेट कोक पर विचार किया गया है। विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र बढ़ाए जाने के समर्थन में कोई कारण अथवा औचित्य नहीं दिया गया है। इसी समय, याचिकाकर्ता द्वारा कहा गया है कि जापान से आयात किए जा रहे मेट कोक में 13% ऐश तत्व हैं। यह समझना कठिन है कि विचाराधीन मेटकोक के ऐश तत्व को 18% तक क्यों रखना चाहिए जब कि आयातित मेट कोक में मात्र 13% तक ऐश तत्व है।

निर्यातक निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्ता ने शामिल उत्पाद का पूर्ण विवरण नहीं दिया है। निम्नलिखित मानदंड मेटकोक का विवरण देते हैं :-

- (क) नमी;
- (ख) ऐश;
- (ग) आकार;
- (घ) वाष्पशील सामग्री;
- (ङ.) निर्धारित कार्बन;
- (च) सल्फर;
- (छ) फॉस्फोरस;
- (ज) एम 40;
- (झ) एम 10; और
- () ऐश संगलन तापमान।

याचिकाकर्ता ने मात्र ऐश तत्व को मानदंड के रूप में मान्यता दी है।

जहाँ ऐश तत्व एवं उत्पाद में तथा उसके उपयोग में इसके महत्व के मुद्दे को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा मान्यता दी गई है और सुलझाया गया है, वहीं मेट कोक में नमी तत्व तथा उसकी संगतता के मुद्दे को मान्यता प्रदान करने की आवश्यकता है।

न केवल उत्पादन बल्कि बिक्री के दृष्टिकोण से भी मेटकोक में "नमी" एक अपरिहार्य तत्व है। इसके साथ ही अधिक नमी तत्व का अर्थ है वस्तु में जल की अधिक तथा मेट कोक की कम मात्रा का होना। अतः अदर्श रूप से उपभोक्ता नमी रहित तत्व वाले मेट कोक को खरीदना पसंद करेंगे। तथापि उत्पाद में न्यूनतम नमी तत्व का होना अपरिहार्य है। नमी तत्व की संगतता इतनी अधिक है कि नमी तत्व के उच्चतम सीमा से अधिक हों जाने की स्थिति में उत्पादक को बिक्री मूल्य के विचार से कटौतियों के रूप में दंड का भुगतान करना होगा।

iv) पाटन एवं क्षति

- भारत के लिए निर्यात कीमत में कई बार प्रहस्तन के कारण नमी तत्व शुल्कों के लगने और नमी घटक को गणना में शामिल किया जाना चाहिए। जापान से मेट कोक के निर्यातों में निम्नलिखित प्रहस्तन तो शामिल है ही :-

1. उत्पादन के पश्चात इकट्ठा करना;
2. लदान पत्तन पर जलयान में सामग्री का लदान;
3. उतराई पत्तन पर सामग्री को उतारना;
4. उतराई पत्तन से सामग्री को उपभोक्ता के भंडार स्थलों में स्थानान्तरित करना; और
5. भंडार स्थल से उत्पादन विभाग में ले जाना।

इसकी तुलना में, जापान में सामग्री की घरेलू बिक्री में मात्र 1, 4 और 5 चरण शामिल हैं। अतः सामग्री के निर्यातों में प्रहस्तन के कम से कम दो अतिरिक्त चरण शामिल हैं। चूँकि निर्यातों के मामले में प्रहस्तन चरणों की संख्या अधिक है, इसलिए शुल्क अधिक लगते हैं।

- विश्वभर में मेटकोक की कमी के वर्तमान परिदृश्य में जापान या किसी अन्य देश द्वारा पाटन किए जाने की कोई संभावना नहीं है ।
- पिग आयरन का देशी उत्पादन करने और गौण इस्पात क्षेत्र को कार्यक्षम और प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से सरकार ने मिनी ब्लास्ट फर्नेसेज, जिनमें देशी लौह अयस्क प्रयोग किया जाता है तथा जिनसे इस्पात बनाने में निजली की भारी बचत होती है, की स्थापना को प्रोत्साहित किया था । पिछले दशक के दौरान 3000-4000 करोड़ रुपये के निवेश से प्रतिवर्ष 3.5 मिलियन टन से अधिक गर्म धातु की क्षमता वाली मिनी ब्लास्ट फर्नेसेज की स्थापना की गई है जिसमें 100,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है ।
- लो ऐश मेटलर्जिकल कोक जिसमें कम गंधक और कम फास्फोरस होता है मिनी ब्लास्ट फर्नेस उद्योग के लिए आधारभूत निविष्टी है । यह ब्लास्ट फर्नेस रूट के माध्यम से इस्पात/पिग आयरन की उत्पादन लागत का 60-70% से अधिक है । मिनी ब्लास्ट फर्नेस को सालाना वांछित रसायन वाले लो ऐश मेटलर्जिकल कोक की 2.5 मिलियन टन की आवश्यकता होती है । ब्लास्ट फर्नेस उद्योग द्वारा वांछित मेटलर्जिकल कोक की वांछित मात्रा घरेलू स्रोतों से अत्यधिक नगण्य होने के कारण मिनी ब्लास्ट फर्नेस उद्योग मेटलर्जिकल कोक के आयातों पर पूरी तरह से आश्रित है ।
- मिनी ब्लास्ट उद्योग कभी भी घरेलू कोक उत्पादन बाजार और घरेलू उद्योग के प्रमुख ग्राहक का हिस्सा नहीं रहा है । इस्पात सचिव द्वारा 26 नवम्बर, 1999 को की गई बैठक में इण्डियन मेटलर्जिकल कोक मैनयुफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईएमसीओएम) ने बताया कि ब्लास्ट फर्नेस इकाईयां कोक उत्पादकों के प्रमुख बाजार नहीं हैं । आईएमसीओएम इस बात से भी सहमत हुआ था कि ब्लास्ट फर्नेस इकाईयों की पाटनरोधी शुल्क से छूट मिनी ब्लास्ट फर्नेस उद्योग के बने रहने के लिए अति आवश्यक है । आईएमसीओएम ने बताया कि उनको कोई आपत्ति नहीं है यदि सरकार ब्लास्ट फर्नेस उद्योग को पाटनरोधी शुल्क की सीमा से छूट देती है । इन तथ्यों पर विचार करते हुए, सरकार ने अधिसूचना संख्या 69/2000-सीयूएस दिनांक 19.05.2000 जारी करते समय ब्लास्ट फर्नेसेज का प्रयोग करने वाले इस्पात या पिग आयरन के विनिर्माताओं को चीनी मूल के मेटलर्जिकल कोक पर पाटनरोधी शुल्क की सीमा से बाहर कर दिया था वशत कि यह सीमाशुल्क (उत्पादन शुल्क लगाने योग्य वस्तुओं के विनिर्माण के लिए रियायती शुल्क दर पर वस्तुओं का आयात) नियमावली, 1996 में निर्दिष्ट प्रक्रिया

का पालन करता हो। यह सुविधा अधिसूचना सं० 100/2002-सीमाशुल्क दिनांक 01.10.2002 के तहत कोरेक्स प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाले इस्पात विनिर्माताओं को भी दी गई थी।

- मिनी ब्लास्ट फर्नेस उद्योग द्वारा अपेक्षित लो ऐश मेटकोक से संबंधित वर्तमान में प्रचलित तथ्यों के संदर्भ में जापानी मूल के मेटकोक पर पाटनरोधी शुल्क लगाना न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय। इससे मिनी ब्लास्ट उद्योग को भारी नुकसान होता है और साथ ही यह घरेलू उद्योग को कोई सुरक्षा भी प्रदान नहीं करता है। कोरेक्स प्रौद्योगिकी के तहत मिनी ब्लास्ट फर्नेस उद्योग और इस्पात उत्पादक इकाइयों को पाटनरोधी शुल्क की सीमा से बाहर कर दिया जाना चाहिए। मिनी ब्लास्ट फर्नेस उद्योग को एक विशेष प्रकार के मेटकोक की आवश्यकता होती है और इसलिए "समान वस्तु" का निर्णय करते समय मेटकोक के विनिर्देशन का विस्तृत ब्योरा देना पड़ता है क्योंकि मेटकोक की गुणवत्ता अनेक मापदंडों पर निर्भर करती है।

भारतीय फेरो एलोय उत्पादक एसोसिएशन

जहां तक विचाराधीन उत्पाद, घरेलू उद्योग के क्षमता प्रतिबंध, कैप्टिव खपत, जांच अवधि के पश्चात कीमत संरचना आदि का संबंध है, अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए अधिकांश तर्कों को दाहराते हुए एसोसिएशन ने फेरो एलोय उद्योग से संबंधित निम्नलिखित और निवेदन किए हैं :-

- कि विशेष लो ऐश और लो फोस कोक घरेलू रूप से उपलब्ध नहीं है और फेरो एलोय उत्पादकों को इसके लिए आयातों पर आश्रित रहना पड़ता है।
- कि भारतीय मेटकोक उत्पादकों ने पहले यह स्वीकार किया है कि फेरो एलोय उत्पादकों और पिग आयरन उत्पादकों को किए गए आयात उनको कोई क्षति नहीं पहुँचाते हैं और भारत सरकार ने पहले दो अधिसूचनाओं के जरिए चीन के मामले में इन प्रयोक्ताओं द्वारा किए गए आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की छूट दे दी है। केवल इसके कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के लिए कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।
- किसी स्थिति में, निर्दिष्ट प्राधिकारी परिवर्तनशील आधार (संदर्भ कीमत आधार) पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते रहे हैं और ऐसी संदर्भिका कीमत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारतीय ग्राहक सामग्री को अनुचित रूप से ऊँची कीमतों पर आयात करने के लिए बाध्य न हो।

घ. प्राधिकारी द्वारा जांच

निर्यातकों, आयातकों और याचिकाकर्ता द्वारा किए गए उपर्युक्त अनुरोधों, जिस सीमा तक ये नियमानुसार संगत हैं और इस मामले पर प्रभाव डालते हैं, की जांच की गयी है और विचार किया गया है तथा इन जांच परिणामों में उचित स्थानों पर कार्रवाई की गयी है ।

1. विचाराधीन उत्पाद

जांचाधीन याचिका में यथा वर्णित उत्पाद जापान मूल का अथवा वहां से निर्यातित 18% से कम ऐश तत्व वाला मैटेलर्जिकल कोक (जिसे मैटकोक भी कहा गया है) है ।

मैटकोक का उत्पादन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, उच्चताप (जोकि सामान्यतया करीब 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है) पर बिना कोयले को जलाए हुए मैटेलर्जिकल (कोकिंग) कोयला के विनाशक आसवन द्वारा होता है । उत्पादित मैटेलर्जिकल कोक मुख्यतया कार्बन है जिसके साथ कुछ खनिज और अवशिष्ट अस्थिर पदार्थ होते हैं । मैटकोक का उपयोग उन उद्योगों में प्रमुख ईंधन के रूप में होता है जहां भट्टों या घमन भट्टियों में एक समान और उच्च तापमान की जरूरत होती है ।

मैटकोक सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 27 (उपशीर्ष 27.04 के अंतर्गत) वर्गीकृत है । मैटकोक वस्तु का आयात ओ जी एल के अंतर्गत किया जा सकता है और इस पर 15% मूल सीमाशुल्क लगता है । तथापि यहां बताए गए उत्पाद का वर्गीकरण, विनिर्माण प्रक्रिया और उपयोग केवल संकेतात्मक है और ये विचाराधीन उत्पाद के कर्मक्षेत्र पर किसी प्रकार बाध्यकारी नहीं हैं । मैटकोक (संबद्ध मैटकोक समेत) का उपयोग पिग आयरन, फाउंडरीज़, फ़ैरो एलॉयज़, कैमिकल, समेकित इस्पात संयंत्रों एवं अन्यो समेत विभिन्न उद्योगों में किया जाता है ।

प्राधिकारी याचिकाकर्ताओं के दावों को नोट करते हैं कि जापान से आयातित संबद्ध कोक में 13% से कम ऐश तत्व वाले कोयले का प्रयोग किया जाता है । कोकिंग की प्रक्रिया में कोयले में अस्थिर पदार्थ जल जाते हैं अथवा उनका अर्क निकल जाता है और इस प्रकार

अवशिष्ट कोक में ऐश के तत्व में उसी प्रतिशत में वृद्धि होती है जिस प्रतिशत में कोयले में अस्थिर पदार्थों की होती है । इस प्रकार, 13% ऐश तत्व और 24-25 अस्थिर पदार्थ से 18%, ऐश तत्व वाले कोक का सृजन होता है और भारत में केवल 18% तक के संबद्ध मैटकोक का आयात किया जा रहा है । अतः 18% से कम ऐश तत्व वाले मैटकोक को इस मामले में जांच के अध्याधीन रखा जाना चाहिए ।

तथापि, प्राधिकारी यह बात भी नोट करते हैं कि जापान से आयातित कोक में लगभग 13 ऐश होता है । इस मामले में घरेलू उत्पादक और याचिकाकर्ता भी केवल 15% से कम ऐश तत्व वाले कोक का विनिर्माण करते हैं। घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद के भीतर उस माल को शामिल किए जाने का अनुरोध कर सकता है जिसका वास्तव में आयात किया गया है और क्षति पहुंचायी है। इस संबंध में प्राधिकारी चीन से मैटकोक की पाटनरोधी जांच से संबंधित प्रारंभिक एवं अंतिम जांच परिणामों में विस्तृत जांच एवं वार्ताओं का स्मरण करते हैं (दिनांक 27 अगस्त 1998 की अधिसूचना सं. 8/2/97-एडीडी द्वारा) उपर्युक्त जांच परिणामों में सभी व्यक्त विचारों और कम ऐश मैटकोक के प्रयोग संबंधी तकनीकी विचारों और डीजीएफटी के निविष्टि उत्पादन संबंधी मानदण्डों का भी हिसाब में लेने के पश्चात् प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला था कि 15% अथवा उससे कम ऐश तत्व घरेलू कोयला जिसमें ऐश का प्रतिशत अधिक होता है, से उत्पादित मैटकोक को कम ऐश वाले मैटकोक से अलग करने हेतु उचित संकेतक है । अतः प्राधिकारी ऐसी कोई वजह नहीं पाते हैं कि वर्तमान जांच का विस्तार 18% तक ऐश तत्व वाले मैटकोक तक क्यों किया जाए । 18% से कम ऐश तत्व वाले मैटकोक को शामिल करने हेतु घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त कारण किसी अतिरिक्त तथ्यों एवं कारणों पर आधारित प्रतीत नहीं होता है । केवल जापानी उत्पादक 13% तक ऐश तत्व वाले कोयले का प्रयोग करते हैं, स यह सिद्ध नहीं हो जाता है कि जापान से निर्यातित कोक में 18% तक ऐश तत्व होगा अतः इसे विचाराधीन उत्पाद माना जाए ।

अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद में जापान मूल के अथवा से निर्यातित 15% से कम ऐश तत्व वाला मैटकोक शामिल होगा (जिसे इसमें एवं पश्चात् संबद्ध मैटकोक कहा गया है) ।

(2) समान वस्तु

15% से कम ऐश तत्व वाले निम्न ऐश मैटकोक तक जांच सीमित करने का निर्णय लेने के पश्चात् प्राधिकारी घरेलू उद्योग की स्थिति का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ और निर्यातक देश में 'सामान्य' मूल्य का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ 'समान वस्तु' का निर्धारण करने की कार्यवाई करते हैं ।

पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (घ) में यह परिभाषित है कि "समान वस्तु" का अर्थ उस वस्तु से है जो भारत में पाटन की जा रही जांचाधीन वस्तु से सभी मामलों में मिलती जुलती अथवा उसके सादृश्य है अथवा ऐसी वस्तु के अभाव में दूसरी ऐसी वस्तु जो हालांकि सभी मामलों में एक समान नहीं है, जिसमें जांचाधीन उत्पादों से मिलनी जुलती विशेषताएं हैं ।

इस मामले में विचाराधीन वस्तु 15% से कम राख वाला मैटकोक है । घरेलू उद्योग का यह दावा कि वे आयातित कोयला (मुख्यतः आस्ट्रेलिया से) कम राख वाले मैटकोक का उत्पादन करते हैं । अन्य उत्पादकों, जो आई सी ए के सदस्य हैं, द्वारा उत्पादित मैटकोक, में या तो घरेलू कोयला जिसमें राख का प्रतिशत काफी अधिक होता है, का प्रयोग होता है अथवा आयातित कोयले के साथ इसका मिश्रण करते हैं । परिणामी कोक में राख की मात्रा (15% से अधिक) अधिक होती है ।

संबद्ध देश से आयातित कोक में 15% से कम राख होती है और यह याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित घरेलू कोक का तकनीकी और वाणिज्यिक प्रतिस्थापन है । अतः इसे समान उत्पाद समझा जाना है । प्राधिकारी याचिकाकर्ताओं के इन दावों को भी नोट करते हैं कि वे कम राख वाले मैटकोक की सभी किस्मों और ग्रेडों का उत्पादन कर सकते हैं । याचिकाकर्ताओं ने यह दावा भी किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित मैटकोक और संबद्ध देश से निर्यातित मैटकोक, जिसका कीमत पर प्रभाव पड़ सकता है, के बीच कोई अन्तर नहीं है ।

तथापि निर्यातकों एवं आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित कम राख वाले मैटकोक और संबद्ध देश से आयातित मैटकोक अनेक तकनीकी मानदंडों जैसे नमी तत्व, अस्थिर सामग्री, सल्फर, फोस एम 40 और एम 10 शक्ति इत्यादि पर तुलनीय नहीं है। अतः वे वस्तुतः तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं हैं। विभिन्न प्रयोगों के लिए अपेक्षित मैटकोक की तकनीकी विनिर्दिष्टताओं विशेषकर इसमें सल्फर और फॉस्फोरस तत्व में अन्तर है। घरेलू उत्पादक जैसे उद्योगों और पिग आयरन विनिर्माताओं के लिए सही किस्म का मैटकोक (कम फोस और कम सल्फर) और सही आकारों के मैटकोक का उत्पादन करने में असफल रहे हैं। तथापि याचिकाकर्ताओं का यह दावा कि उपभोक्ताओं ने उनके द्वारा उत्पादित मैटकोक का और आयातित मैटकोक के साथ मिश्रित मैटकोक का अदल-बदल कर प्रयोग किया है।

प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि मेटलर्जीकल कोक का विनिर्माण कोक ओवनों में कोकिंग विनाशक आसवन द्वारा किया जाता है और कोक की गुणवत्ता उस कोयले पर निर्भर होती है जो इस प्रक्रिया में केवल कच्ची सामग्री होती है। कोक में राख की मात्रा, सल्फर और फॉस्फोरस की मात्रा प्रयोग किए जा रहे कोयले पर और कोयले में इन सामग्रियों की मात्रा पर निर्भर करता है। जहां तक कोक की गुणवत्ता का संबंध है, उन कुछेक रिकवरी संयंत्रों को छोड़कर कोई अन्य प्रौद्योगिकी संबंधी मुद्दा नहीं है, जहां इन ओवनों में समतल भरण के लिए कोयले के ब्लाक बनाने के लिए स्टैपिंग उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। इससे कोयले की बेहतर कोकिंग होती है और परिणामी उत्पाद अधिक मजबूत होता है। रिकवरी संयंत्र कोयले में वाष्पशील पदार्थ एकत्र हो जाते हैं जो प्रयोग किए जा रहे कोयले के आधार पर भिन्न-भिन्न होता है। इस प्रकार से संग्रहित कोक ओवन गैस को विभिन्न सह-उत्पादों की प्राप्ति हेतु आगे प्रसंस्कृत किया जाता है अथवा उसका उपयोग कोक ओवनों को गरम करने, विद्युत उत्पादन आदि के लिए ईंधन के रूप में हानिकर पदार्थों को निकालने के बाद किया जा सकता है। तथापि, परिणामी कोयले में राख की मात्रा और सल्फर तथा फॉस्फोरस जैसे अन्य रसायन प्रयुक्त कोयले के प्रकार पर निर्भर होते हैं।

इस संबंध में प्राधिकारी 27 अगस्त 1998 की अधिसूचना सं. 8/2/97-एडीडी के तहत चीन से मैटकोक के मामले में अंतिम जांच परिणामों में 'समान वस्तु' के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा का स्मरण करते हैं। उक्त मामले में विस्तृत चर्चा के बाद यह माना था कि _____ "कम राख की मात्रा वाले मैटकोक के उत्पादन को ही चीन से आयातित कोक के 'समान वस्तु' माना जाता है। निर्यातकों और आयातकों के इस तर्क में भी काफी दम है कि उच्च राख वाले मात्रा वाले मैटकोक को समान वस्तु माना जाना चाहिए और उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनज़र स्वीकार किया जाता है।"

"उपर्युक्त के अलावा, प्राधिकारी की राय यह भी है कि विदेश व्यापार महानिदेशालय के मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों में पिग आयरन (ब्लास्ट फर्नेस) के उत्पादन हेतु दर्शायी गयी निविष्टियों में से एक निविष्टि राख की कम मात्रा वाला मैटकोक (15% से कम राख की मात्रा वाला) है। अतः प्राधिकारी निर्यातकों / आयातकों की इस बात को मानने के लिए बाध्य हुए हैं कि 15% और उससे कम राख की मात्रा वाला मैटकोक ही चीन से आयातित कोक के 'समान वस्तु' है भले ही भारत में उसका उत्पादक कोई भी हो। अतः प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि भारत में उत्पादक पर ध्यान दिए बिना 15% और उससे कम राख की मात्रा वाला मैटकोक चीन से आयातित कोक के 'समान वस्तु' है।"

मैटकोक की विनिर्माण प्रक्रिया और इसी प्रकार के मामले में प्राधिकारी द्वारा पहले निपटाए गए मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी यह मानते हैं कि भारत में उत्पादक पर ध्यान दिए बिना 15% और उससे कम राख की मात्रा वाला मैटकोक जापान से आयातित राख की इतनी ही मात्रा वाले कोक के 'समान वस्तु' है।

तथापि प्राधिकारी इंडियन मिनी ब्लास्ट फर्नेसिज़ एण्ड इंडियन फ़ैरो एलॉयज़ इंडस्ट्रीज़ के इन तर्कों को नोट करते हैं कि इन उद्योगों द्वारा अपेक्षित और इस प्रकार उनके द्वारा आयातित कोक घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित कोक से भिन्न है और इसलिए उसे पाटनरोधी शुल्क से छूट प्रदान की जानी चाहिए।

फैरो एलॉयज इंडस्ट्री ने अनुरोध किया है कि उनके द्वारा अपेक्षित कोक भिन्न-भिन्न विनिर्देशन का है। उन्हें केवल 10-30 एम एम के आकार श्रेणी वाले कोक की आवश्यकता होती है और जिसमें फॉस्फोरस तत्व का 0.0166% से अधिक न हो। भारतीय कोयले से उत्पादित कोक में 0.15% से अधिक का फॉस्फोरस तत्व होता है और फैरो एलॉय उत्पादक किसी भी प्रकार इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा आयातित कोयले से उत्पादित कोक और अन्य उत्पादकों अर्थात् आई सी ए, धनबाद से सदस्यों द्वारा उत्पादित घरेलू कोयला उच्च ऐश और फॉस्फोरस तत्व के कारण फैरो एलॉय उत्पादकों के लिए उपयुक्त नहीं है। फैरो एलॉय का निविर्माण एक सतत् प्रक्रिया है और इसलिए संयंत्र को बिना किसी व्यवधान और रुकावट के लगातार चलाना होता है। फैरो एलॉय उद्योग को कठोर विशेषताओं वाले कम ऐश, कम फॉस्फोरस, कम सल्फर मैटकोक की आवश्यकता होती है जो कि देशी स्रोतों से उपलब्ध नहीं है। इसके कारण इस उद्योग को संबद्ध देश सहित विभिन्न देशों से कम फॉस्फोरस, कम ऐश और कम सल्फर वाले मैटकोक का आयात करना पड़ता है क्योंकि देशी मैटकोक का उपयोग फैरो एलॉय के उत्पादन के लिए नहीं किया जा सकता है।

एसोसिएशन ऑफ इंडियन मिनी ब्लास्ट फर्नेसेज ने भी इन आधारों पर पाटनरोधी शुल्क से छूट के लिए ऐसा ही निवेदन किया है कि मिनी ब्लास्ट फर्नेसेज के लिए आधार आवश्यकता अलग है और घरेलू उद्योग इस क्षेत्र की भारी मांग को पूरा करने में असफल रहा है। मांग अड़चन पहलू पर इन जांच परिणामों में अलग से विचार किया गया है।

'समान वस्तु' के निर्धारण के लिए विचाराधीन छोटा मुद्दा यह है कि क्या संबद्ध देश से निर्यात किया जा रहा है और इन प्रयोक्ताओं द्वारा आयात किया जा रहा कोक तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्माण किए जा रहे कोक से प्रतिस्थापनीय है और इसलिए यह 'समान उत्पाद' की परिभाषा के भीतर आता है।

जहां तक फैरो एलॉय उद्योग की आवश्यकताओं का संबंध है, इस उद्योग द्वारा आयात किया जा रहा कोक कम ऐश और कम फॉस्फोरस और कम सल्फर तत्व वाला है। ये उद्योग

ऐसे किसी कोक का उपयोग नहीं कर सकते हैं, जो कठोर विशेषताओं विशेषकर फॉस्फोरस तत्व की, से मेल न खाते हों ।

यह फैरो एलॉय उद्योग का मामला है कि वांछित विनिर्देशन के कम फॉस और कम सल्फर के मैटकोक का घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन नहीं किया जा रहा है और पाटनरोधी शुल्कों के बावजूद उन्हें इसका आयात करना पड़ता है । उन्होंने दावा किया है कि उनकी आवश्यकता के लगभग 98% का आयात किया जाता है जबकि चीनी मैटकोक पर पाटनरोधी शुल्क लागू है क्योंकि आमतौर पर भारतीय उत्पादक इस मैटकोक का उत्पादन नहीं करते हैं । घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि फैरो एलॉय इंडस्ट्री द्वारा प्रयोग किया जा रहा कोक उनके द्वारा उत्पादित किया जा सकता है क्योंकि कोक और ऐश की गुणवत्ता उसमें मौजूद फॉस्फोरस और सल्फर तत्व प्रयोग किये जा रहे कोयले की गुणवत्ता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं और कोई अन्य तकनीकी मुद्दा इसमें शामिल नहीं है ।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि फैरा एलॉय उद्योग द्वारा अपेक्षित ग्रेड के कोक का उत्पादन करना घरेलू उद्योग के लिए तकनीकी रूप से संभव है तथापि इसने इस ग्रेड के मैटकोक का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं किया है और आयात आंकड़े दर्शाते हैं कि इस प्रकार के अधिकतर मैटकोक का विगत में आयात किया गया है जबकि इस पर पाटनरोधी शुल्क लागू थे। यह भी तथ्य है कि इन प्रयोक्ताओं द्वारा आयातित मैटकोक के ग्रेड को किसी भी तरीके से घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित किए जा रहे मैटकोक द्वारा स्थानापन्न नहीं किया जा सकता है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि इस खण्ड की कुल मैटकोक (कम ऐश और कम फॉस वाले) की आवश्यकता बहुत कम है और घरेलू उत्पादकों के लिए वाणिज्यिक रूप से यह व्यवहार्य नहीं होगा कि वे इस ग्रेड के मैटकोक का विनिर्माण करने के लिए विशेष प्रकार के कोयले का आयात करें ।

चीन से मैटकोक के आयात में शामिल पूर्ववर्ती मामले में विचार-विमर्श के लिए विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्राधिकारी का भी ध्यान आकर्षित किया गया था । कतिपय प्रयोक्ताओं की विशेष आवश्यकताओं का मुद्दे पर पूर्ववर्ती मामले में विचार-विमर्श किए गए थे और

प्राधिकारी ने नोट किया था कि : "कुछ प्रयोक्ता उद्योग समूहों, जैसे तन्य लोहे के पाअपों, फैरो एलॉय के विनिर्माताओं ने यह उल्लेख किया है कि उनके द्वारा अपेक्षित मैटकोक में कुछ अन्य भौतिक और रासायनिक विशेषताएं होनी चाहिए । उदाहरण के लिए डक्टाइल आयरन पाइप उद्योग द्वारा अपेक्षित मैटकोक में फॉस्फोरस तत्व 0.035% से कम होना चाहिए । जबकि यह समझा जाता है कि कुछ उद्योगों की विशेष आवश्यकताएं हो सकती हैं पाटनरोधी नियम विशिष्ट अन्तिम प्रयोक्ताओं के आधार पर विश्लेषण करने की अनुमति नहीं देते हैं जबकि प्रयोक्ता उद्योगों की विभिन्न किस्मों के बीच उच्च डिग्री का प्रतिस्थापन संभव है । इस प्रकार प्राधिकारी विशेष आवश्यकताओं वाले प्रयोक्ताओं के लिए कोई अलग से श्रेणी बनाने की स्थिति में नहीं हैं ।"

इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि पूर्ववर्ती मामले में विवाद विशेष उद्योगों के लिए अंतिम प्रयोग पर आधारित छूट देने के लिए था और प्राधिकारी का यह निर्णय उचित था कि उसे अंतिम प्रयोग आधारित छूट देने का नियमों के अंतर्गत कोई अधिकार नहीं है । तथापि समान उत्पाद मुद्दे के बारे में फैरो एलॉय उद्योग के तर्क में काफी दम है और इसलिए प्राधिकारी इन पार्टियों के तर्कों को स्वीकार करने को बाध्य हुआ है कि उनके द्वारा प्रयोग किया जा रहा उत्पाद तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित किए जा रहे उत्पाद का स्थानापन्न नहीं है और इसलिए इसे जांच के दायरे से अलग रखना चाहिए ।

इस प्रकार प्राधिकारी का यह मानना है कि फैरा एलॉय उद्योगों द्वारा मुख्य रूप से उपयोग किये जा रहे और संबद्ध देश से आयातित कम ऐश (15% तक) और कम फॉस (0.035% तक) और कम सल्फर (0.5% तक) वाले मैटकोक को तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से घरेलू तौर पर उत्पादित मैटकोक के स्थान पर उपयोग में नहीं लाया जा सकता है और इसे नियमों के अन्तर्गत यथा परिभाषित पदावली के अर्थ के भीतर "समान उत्पाद" नहीं माना जाना चाहिए ।

अंतिम प्रयोग पर आधारित छूट

जहां तक अंडियन मिनी ब्लास्ट फर्नेसेज का संबंध है उनका पूरा तर्क इन आधारों पर अंतिम प्रयोग पर आधारित छूट पर आधारित है कि मांग आपूर्ति अंतर के कारण घरेलू उद्योग इस क्षेत्र द्वारा अपेक्षित मात्रा और गुणवत्ता की आपूर्ति करने में असफल रहा है और इसजिए इन आयातकों को घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले के रूप में नहीं माना जाना चाहिए । इस संबंध में उन्होंने घरेलू उद्योग और मिनी ब्लास्ट फर्नेसेज द्वारा इस क्षेत्र को पाटनरोधी शुल्क से बाहर रखने के एक करार के कार्यवृत्त का उल्लेख किया है । प्रयोक्ताओं ने तर्क दिया है कि इस करार के आधार पर और इंडियन मिनी ब्लास्ट फर्नेसेज को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पूर्ववर्ती मामले में सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25(1) के अंतर्गत दिनांक 19.5.2000 की अधिसूचना सं. 69/2000 के द्वारा वास्तविक प्रयोक्ता आधार पर इस क्षेत्र को पाटनरोधी शुल्क से छूट दी थी तथापि घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि उचित समय पर राष्ट्रीय हित में ऐसा करना समीचीन हो सकता है कि क्षमता संबंधी आरंभिक अड़चन आने पर ब्लास्ट फर्नेस और फैंरो एलॉयज के प्रयोक्ताओं को छूट प्रदान की जाए । किन्तु इस बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता कि इस छूट से घरेलू उद्योग को आज हो रही क्षति को संबल मिला है । इसके परिणामस्वरूप क्षमता को बढ़ाने की प्रक्रिया धीमी हुई है । अब जिस घरेलू उद्योग ने क्षमता में पर्याप्त वृद्धि कर ली है और जो नए कोक संयंत्रों की स्थापना कर रहा है, उसे क्षमता संबंधी अड़चनों के आधार पर इस क्षेत्र को छूट देने का कोई मामला नहीं बनता है । याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया है कि पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते समय प्राधिकारी के पास प्रयोक्ताओं के कुछ वर्ग को छूट देने की कोई शक्ति नहीं है क्योंकि पाटनरोधी नियमावली के नियम 19 में यह उल्लेख है कि नियम 13 अथवा 18 के अंतर्गत कोई शुल्क भेदाभाव रहित आधार पर जगाया जाएगा और वह ऐसी वस्तु के सभी आयातों पर लागू होगा चाहे पाटन का स्रोत कोई भी हो और जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है । परंतु इसमें इन स्रोतों से हुए ऐसे आयातों का मामला शामिल नहीं है जिसमें नियम 15 के अनुसार वचनपत्र स्वीकार किया गया है ।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि लघु ब्लास्ट फर्नेसों के लिए 20-50 मिमी. के बीच के आकार के कम ऐश वाले मैटकोक (15% से कम ऐश तत्व वाले) की ज़रूरत होती है । घरेलू

उद्योग द्वारा विनिर्मित कोक इन विनिर्देशनों के अनुरूप है और इस प्रकार वह संबद्ध देश से आयात किए जा रहे मैटकोक से वाणिज्यिक एवं तकनीकी दोनों रूपों में प्रतिस्थापनीय है । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सीमाशुल्क अधिनियम के संगत उपबंधों के अंतर्गत भारत सरकार के सर्वोपरि क्षेत्राधिकार के भीतर राजस्व विभाग द्वारा पूर्ववर्ती मामले में उद्योग के एक खण्ड को पाटनरोधी शुल्क से प्रदान की गई छूट का इस मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है

अतः प्राधिकारी अंतिम निर्धारण होने तक प्रारंभिक निर्धारण के प्रयोजनार्थ ऊपर उल्लिखित फैरा एलॉय उद्योग द्वारा प्रयुक्त कम ऐश, कम फॉस कोक को छोड़कर घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से निर्यातित वस्तु नियम 2(घ) के अर्थ के भीतर समान वस्तु है ।

(3) घरेलू उद्योग और उसका आधार

यह याचिका घरेलू उद्योग की ओर से इंडियन मेटलर्जिकल कोक एसोसिएशन (आई एम सी ओ एम ए) द्वारा दायर की गई है । छः घरेलू उत्पादक याचिका की पार्टी और मै. गुजरात एन आर ई कोक लि. ने याचिका का समर्थन किया है । ये इकाईयां 15% से कम ऐश तत्व के कम ऐश वाले मैटकोक का विनिर्माण करती हैं और इन इकाईयों का (जांच अवधि के दौरान) सम्मिलित उत्पादन *** मी. टन रहा है ।

इसके अलावा मैटकोक के ऐसे अन्य विनिर्माता (आई.सी.ई.ए. के सदस्य) हैं जो उच्च ऐश तत्व वाले कोक का विनिर्माण करते हैं और इसलिए वे "समान वस्तु" के उत्पादकों के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग में शामिल किए जाने की पात्रता नहीं रखते हैं । ऐसे अन्य उत्पादक अर्थात् समेकित इस्पात संयंत्र भी हैं जो कैस्टिव खपत हेतु अपने खुद की जरूरत के अनुसार अलग-2 ऐश तत्व वाले मैटकोक का उत्पादन करते हैं । इस संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि नियम 2(ख) के तहत "घरेलू उद्योग" की परिभाषा निम्नानुसार है इ

"घरेलू उद्योग का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु का विनिर्माण और उससे जुड़ा कोई कार्यकलाप करते हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त

वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है किन्तु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उस वस्तु के आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का भाग नहीं माना जाएगा ।"

"बशर्ते कि नियम 11 के उपनियम (3) में उल्लिखित आपवादिक परिस्थितियों में, जांचाधीन वस्तु से संबंध में घरेलू उद्योग में दो या इससे अधिक प्रतिस्पर्धी बाजार शामिल और ऐसे प्रत्येक बाजार के उत्पादकों को एक अलग उद्योग माना जाएगा यदि :-

- (i) ऐसे किसी बाजार के उत्पादक जांचाधीन वस्तु के अपने पूरे या लगभग पूरे उत्पादन को इसी बाजार में बेचते हों ; या
- (ii) ऐसे बाजार में मांग की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति क्षेत्र में कहीं और स्थित उक्त वस्तु के उत्पादकों द्वारा न की जाती हो ।"

इन आइ.एस.पी या कैप्टिव उत्पादकों द्वारा उत्पादित कोक मूल रूप से इन इकाइयों के उत्पादन का कैप्टिव कच्ची सामग्री उत्पादन है और ये घरेलू आजार के वाणिज्य में प्रवेश नहीं करती है और इसजिए उपर्युक्त उप-नियम 3(i) तथा (ii) के अर्थ के भीतर ये घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं है । उनका उत्पादन उपर्युक्त नियमावली के अर्थ के भीतर एक अलग बाजार बनाता है और इसे संबद्ध उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए । इसके अलावा इनमें से कुछ इकाइयां अपनी खपत की अनुपूर्ति करने के लिए सबद्ध मैटकोक का आयात करती हैं ।

निर्दिष्ट प्राधिकारी तथा पाननीय सीगेट ने पूर्ववर्ती मामलों में यह माना है कि कैप्टिव उत्पादकों, जो अपने संपूर्ण उत्पादन का उपयोग करते हैं, को घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं माना जाए । तदनुसार इन उत्पादकों के उत्पादन एवं क्षमता पर घरेलू उद्योग की स्थिति के निर्धारणार्थ विचार नहीं किया गया है ।

अतः प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि याचिकाकर्ता संबद्ध मेटकोक के घरेलू उत्पादन के बड़े हिस्से का निर्माण करते हैं और उनके पास संगत नियमों के अधीन इस याचिका को दायर करने संबंधी योग्यता है ।

जांच अवधि

इस मामले में 15 महीने की जांच अवधि निर्धारित की गई थी जो 1 अप्रैल 2001 से 30 जून 2002 तक की थी । निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षों की यह दलील है कि इस मामले की जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा एक पुरानी जांच अवधि स्वीकृत की गई थी । इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस मामले ने याचिका सितम्बर 2002 में याचिका दायर की गई थी जिसमें 31 मार्च 2002 तक के आंकड़े दिए गए थे । प्राधिकारी के, आंकड़ों में हाल के आंकड़ों को शामिल करके अद्यतन बनाने पर जोर देने पर ही याचिकाकर्ताओं ने 30 जून 2002 तक के आंकड़ों को प्रस्तुत किया था क्योंकि पूर्ण आंकड़े केवल इसी अवधि तक उपलब्ध थे । (प्राधिकारी नोट करते हैं कि करार अथवा पाटनरोधी नियमावली में विशिष्ट उपबंध वाला कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है) । तथापि, डब्ल्यू टी ओ करार संबंधी नोट (अनुच्छेद 2.2.1) में बताया गया है कि जांच अवधि 6 महीने से कम की नहीं होनी चाहिए । इस प्रकार पाटनरोधी कानून के अलग-अलग प्रावधानों में जांच अवधि के संदर्भ में कोई विनिर्देशन या प्रतिबंध नहीं है । तथापि जांच अवधि (पी ओ आई) का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए संगत दिशानिर्देशों में व्यवस्था है कि पाटन एवं क्षति के संबंध में ब्यौरेवार जांच के लिए विचाराधीन अवधि यथासंभव प्रतिनिधिक एवं नवीनतम होनी चाहिए । सर्वाधिक वांछनीय जांच अवधि वित्तीय वर्ष है, बशर्ते कि वित्तीय वर्ष के अंत तथा आवेदन प्रस्तुत करने के बीच तर्कसंगत निकटता हो । इसलिए प्राधिकारी मानते हैं कि याचिका प्रस्तुत करने की तारीख पर नवीनतम उपलब्ध आंकड़े 30 जून तक के थे और तदनुसार जांच अवधि सही ढंग से निर्धारित की गई थी । इसलिए, जांच अवधि को बदलने और वर्तमान जांच के लिए जांच अवधि के बाद के आंकड़ों को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

(4) सामान्य मूल्य एवं निर्यात कीमत

धारा 9 (क) (1) (ग) के अधीन किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है :-

- (i) सामान्य व्यापार के दौरान समान वस्तुओं के लिए उप-धारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथानिर्दिष्ट तुलनात्मक मूल्य जबकि ऐसी वस्तु निर्यातक देश या क्षेत्र में उपभोग के लिए आशियत हो; या
- (ii) जहां निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में सामान्य व्यापार के दौरान समान वस्तु की कोई बिक्री नहीं हो या विशेष बाजार दशा के कारण अर्थात् निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में बिक्रियों की कम मात्रा के कारण, ऐसी बिक्रियों की वजह से समुचित तुलना नहीं हो सकती हो तो सामान्य मूल्य या तो :-
- (क) निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से आयात किए जाने पर समान वस्तु की उप-धारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथा निश्चित तुलनात्मक प्रतिनिधि मूल्य; या
- (ख) उप-धारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथा निश्चित प्रशासनिक बिक्री और सामान्य जागतों एवं लाभों के लिए उचित वृद्धि के साथ वस्तु मूल के देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत;

उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार सामान्य मूल्य एवं कारखाना द्वार कीमत के निर्धारण का वर्णन निम्नानुसार है ।

सामान्य मूल्य

क. मै. जे एफ ई स्टील कॉर्पोरेशन, जापान

प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. जे एफ ई स्टील कॉर्पो., जापान से संबद्ध मैटकोक के उत्पादक तथा निर्यातक हैं और वे मै. मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन तथा अन्य व्यापारिक कंपनियों के जरिए इस उत्पाद का निर्यात भी करते हैं । जे एफ ई एक समेकित इस्पात उत्पादक है और वे ऑस्ट्रेलिया व अन्य देशों से आयातित कोयले में से अपनी खपत के लिए कम राख वाले

मेटकोक का उत्पादन करते हैं। घरेलू बाजार में या निर्यात बिक्रियों के लिए सौदा व्यापार के लिए निकाले गए कोयला इस्पात संयंत्र से अस्वीकृत माल है अर्थात् विशिष्ट आकार के हैं जिनका प्रयोग उनकी अपनी ब्लास्ट भट्टियों में नहीं किया जा सकता है। जे एफ ई कम राख वाले मेटकोक के उत्पादन के लिए रिकवरी टाइप कोयला ओवन का प्रयोग करते हैं और इससे प्राप्त कोयला ओवन गैस का प्रयोग इस्पात निर्माण और अन्य वाणिज्यिक प्रयोगों में किया जाता है। उत्पादकों ने जाँच अवधि के दौरान स्थापित क्षमता और संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत संबंधी ब्योरे उपलब्ध कराए हैं।

जे एफ ई ने जाँच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की बिक्री की मात्रा एवं मूल्य के ब्योरे उपलब्ध कराए हैं। उत्पादक ने यह भी इंगित किया है कि उनके रिकार्ड सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार हैं और यह दावा किया है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण उनकी घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर किया जाता है। इस संबंध में नियम (उप-नियम 2, अनुबंध 1) इस प्रकार हैं :-

निर्यातक देश के घरेलू बाजार में समान उत्पाद की बिक्री या प्रति इकाई उत्पादन लागत (स्थिर एवं परिवर्तनशील) जमा प्रशासनिक, बिक्री एवं सामान्य लागतों से कम कीमतों पर तीसरे देश को की गई बिक्रियों को कीमत के कारण व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में नहीं माना जाए।

प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु की विनिर्माण लागत, बिक्री एवं सामान्य प्रशासनिक व्ययों तथा उत्पादक के रिकवरी टाइप कोक ओवन में उत्पादित उपोत्पादों की प्राप्य लागत की जाँच की है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादक ने कुल कारोबार की तुलना में मेटकोक निर्यातों के अपने कुल एस जी ए व्ययों के काफी कम हिस्से का आवंटन किया है। उत्पादकों द्वारा अपने रिकवरी टाइप कोक ओवनों के लिए बताई गई रिकवरी लागत भारत में समेकित इस्पात संयंत्रों के समान कोक ओवनों की तुलना में काफी अधिक है। इसलिए, सत्यापन होने तक प्रारंभिक निर्धारण तथा अंतिम निर्धारण के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने कारोबार अनुपात के आधार पर उत्पादकों के एस जी ए व्ययों को उचित दंग मानकीकृत किया है। रिकवरी लागत

को भी भारत में कुशल आइ एस पी के आधार पर मानकीकृत किया गया है । इस संबंध में प्राधिकारी चीन से मेटकोक के मामले में अपने स्वयं के निर्णय का स्मरण करते हैं, जिसमें सेल के रिकवरी कारक को विदेशी उत्पादकों के लिए लागत वसूली की अनुमति देने के लिए आधार माना था । अतः प्रारंभिक जाँच परिणामों के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने अंतिम सत्यापन या निर्धारण होने तक इस मामले में भी विनिर्माण लागत निकालने के लिए रिकवरी के उसी कारक को अपनाया है । प्राधिकारी याचिकाकर्ताओं की इस दलील को भी नोट करते हैं कि रिकवरी टाइप कोक ओवन से प्राप्त उपोत्पाद की लागत वसूली से रिकवरी संयंत्र तथा आधारभूत सुविधाओं की स्थापना की पूंजी लागत की प्रतिपूर्ति कर दी जाती है । तथापि सत्यापन और अंतिम निर्धारण होने तक प्राधिकारी रिकवरी कारक को 19.44% पर पूर्व निर्धारित मानते हैं और विनिर्माण लागत और एस जी ए, के परिकलन की प्रक्रिया निम्नानुसार है :-

विनिर्माण लागत और एस जी ए के परिकलन की प्रक्रिया निम्नानुसार है :-

विनिर्माण व्यय :

(जापानी येन प्रति मी. टन)

कच्ची सामग्रियां कोयला @ कोक का **** / मी. टन *****

अन्य : @ *** % *****

उपभोज्य एवं भण्डार *****

सुविधाएं *****

प्रत्यक्ष श्रम *****

विनिर्माण अधिशेष *****

मूल्यहास *****

कुल

19.44% की दर से प्राप्त सह-उत्पाद (-)

कारोबारी आधार पर एसजीए खर्च

बनाने तथा बेचने की कुल लागत

बनाने तथा बेचने की इस औसत लागत की तुलना घरेलू बिक्री कीमतों के साथ की गई है और अधिकतर सौदे बनाने तथा बेचने की औसत लागत से कम के पाए गए। अतः, सत्यापन तथा अंतिम निर्धारण के लंबित रहने तक प्रारंभिक निर्धारण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी घरेलू बिक्री आंकड़ों की उपेक्षा करते हैं और विनिर्माण लागत तथा ***% के उचित लाभ मार्जिन के आधार पर सामान्य मूल्य परिकलित करने के लिए कार्रवाई करते हैं। तदनुसार, सामान्य मूल्य ***** जापानी येन अर्थात् ***** जापानी येन = 1.00 अमरीकी डॉलर की विनिमय दर से ***** अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रीक टन परिकलित हुआ है।

निर्यात कीमत

प्राधिकारी नोट करते हैं और **उत्पादक** मै. जेएफई कॉरपोरेशन ने संकेत किया है कि उनके द्वारा विनिर्मित संबद्ध वस्तु का मित्सुबिशी कॉरपोरेशन तथा डाइचू इत्यादि जैसे विभिन्न व्यापारियों **के जरिए** भारत को निर्यात किया गया है। उत्पादक ने इन ट्रेडिंग कंपनियों, जिन्होंने वापसी आधार पर भारतीय आयातकों को इन वस्तुओं का निर्यात किया है, को अपने बिक्री बीजकों संबंधी आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। इन बीजक मूल्यों के आधार पर औसत निवल निर्यात कीमत **शुष्क** आधार पर ***** अमरीकी डॉलर प्रति मी. टन परिकलित हुई है। चूंकि निर्देशित निर्यात कीमत का दावा कारखाना गत स्तर पर किया गया है, अतः सत्यापन तथा अंतिम निर्धारण के लंबित रहने तक पैकिंग, अंतर्देशीय भाड़ा, बीमा, भंडारण, प्रहस्तन, बिक्री प्रभार, समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, निकासी तथा हैंडलिंग एवं पत्तन प्रभार के

लिए किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं हुई है । प्रारंभिक निर्धारण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने ***** अमरीकी डॉलर प्रति मी. टन की निवल कारखाना गत निर्यात कीमत पर विचार किया है, जैसा कि निर्यातक/ उत्पादक द्वारा वेट शुष्क

आधार पर दावा किया गया था ।

ख. मै. मिल्सुबिशी कॉरपोरेशन, जापान

सामान्य मूल्य

मै. मिल्सुबिशी कॉरपोरेशन, जापान ने निवेदन किया है कि वह मात्र एक ट्रेडिंग कंपनी है और उसके पास संबद्ध वस्तु के लिए कोई विनिर्माण सुविधा नहीं है । तथापि, उन्होंने मै. जेएफई स्टील के लागत आंकड़ों का संदर्भ लिया है, जो संबद्ध वस्तु, जिसका भारत को निर्यात किया जाता है, के मुख्य उत्पादक हैं । अतः प्राधिकारी मुख्य उत्पादक की विनिर्माण एवं बिक्री की लागत तथा इस निर्यातक की घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर इस निर्यातक के लिए सामान्य मूल्य परिकलित करने की कार्रवाई करते हैं ।

विनिर्माण लागत योग उत्पादक का एसजीए योग असंबद्ध व्यापारी को इसकी बिक्री पर विनिर्माता के लिए एक उचित लाभ (***% की दर से) **** प्रति मी. टन परिकलित होता है । इसकी तुलना जापान में निर्यातक की घरेलू बिक्री कीमत से की गई है । चूंकि जापान में निर्यातक की संबद्ध वस्तु की घरेलू बिक्री कीमत विनिर्माण लागत योग उत्पादक के एसजीए से कम है, अतः प्राधिकारी इन बिक्री कीमतों की उपेक्षा करते हैं और उपरोक्त में व्यापारी के लिए *****% की दर से उचित लाभ मार्जिन जोड़ने के बाद सामान्य मूल्य परिकलित करते हैं । अतः इस निर्यातक के लिए सामान्य मूल्य ***** जापानी येन प्रति मी. टन अर्थात् ***** जापानी येन = 1.00 अमरीकी डॉलर की विनिमय दर से **** अमरीकी डॉलर प्रति मी. टन परिकलित होता है ।

निर्यात कीमत

निर्यातक ने निर्यात आंकड़े प्रस्तुत किए हैं जिनके आधार पर निम्न निर्यात कीमत पैकिंग, अंतर्देशीय भाड़ा, बीमा, भंडारण, प्रहस्तन, बिक्री प्रभारों, समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, निकासी तथा हैंडलिंग एवं पत्तन प्रभार को छोड़कर ***** अमरीकी डॉलर प्रति मी. टन परिकलित हुई है ।

ग. जापान के अन्य सभी निर्यातक/उत्पादक

सामान्य मूल्य

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी निर्यातक/उत्पादक ने प्रश्नावलियों का उत्तर नहीं दिया है और प्राधिकारी नोट करते हैं कि समेकित स्टील उद्यम, जो लगभग अपना सारा उत्पादन उत्तरी अमेरिका को निर्यात करते हैं, के अतिरिक्त जापान में मैट कोक का मात्र एक उत्पादक है । अतः प्रारंभिक निर्धारण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी मै. मिल्सुबिशी कॉरपोरेशन के सामान्य मूल्य अर्थात् **** अमरीकी डॉलर प्रति मी. टन को जापान के सभी अन्य निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य के रूप में स्वीकार करते हैं ।

निर्यात कीमत

चूंकि जापान के अन्य निर्यातकों ने सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमतों के लिए कोई आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं इसलिए प्राधिकारी ने आयातकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से निम्नतम निर्यात कीमत निर्धारित करने की कार्यवाई की है और निर्यात कीमत **** अमरीकी डॉलर प्रति मी. टन परिकलित की है ।

पाटन मार्जिन - सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत की तुलना

तुलना संबंधी नियमों में प्रावधान इस प्रकार हैं: -

"पाटन मार्जिन निकालते समय, निर्दिष्ट प्राधिकारी निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य के बीच उचित तुलना करेगा । यह तुलना व्यापार के समान स्तर पर सामान्यता: कारखाना द्वारा स्तर पर की जाएगी और यथा संभव उसी समयावधि के दौरान की गई बिक्रियों के संबंध

में की जाएगी । जो अंतर तुलनीयता पर प्रभाव डालते हैं, उनके लिए प्रत्येक मामले में गुण-दोष के आधार पर समुचित छूट दी जाएगी; अंतर में शामिल है बिक्री की शर्तें, कराधान, व्यापार के स्तर, मात्राएं, वास्तविक विशेषताएं तथा अन्य अंतर जो कीमत तुलनीयता को प्रभावित करने के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं ।"

प्राधिकारी ने संबद्ध देश के सभी निर्यातकों / उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन के मूल्यांकन के लिए जांच अवधि में भारित औसत सामान्य मूल्य की तुलना भारित औसत कारखाना-गत निर्यात कीमत से की है ।

निर्यातकों/ उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार परिकालित होता है : -

निर्यातक	सामान्य मूल्य (एन.वी.) \$/एम.टी	निर्यात मूल्य (ई.पी.)\$/एम.टी.	पाटन मार्जिन	सी.आई.एफ. मूल्य के % रूप में पाटन मार्जिन
1. मै. जे एफ ई सटील कॉर्पोरेशन, जापान	****	****	****	39.63%
2. मै.मिल्सुबिशी कॉरपोरेशन, जापान	****	****	****	39.89%
3. जापान के अन्य सभी निर्यातक/उत्पाद क	****	****	****	53.56%

6. क्षति तथा कारणात्मक संबंध

उपरोक्त नियम 11, अनुबंध - II के तहत क्षति के बारे में कोई निष्कर्ष निकलता है तो इस प्रकार निष्कर्ष में "... .. पाटित आयातों की मात्रा, घरेलू बाजार में समान वस्तु की कीमतों पर उनके प्रभाव तथा इस प्रकार उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए" घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निर्धारण शामिल होगा। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय यह जांच करना आवश्यक समझा जाता है कि पाटित आयातों के कारण भारत में समान वस्तुओं की कीमतों में अन्यथा उल्लेखनीय स्तर तक गिरावट आई है अथवा कीमत वृद्धि में अन्यथा रुकावट आई है जो कि अन्यथा उल्लेखनीय स्तर तक बढ़ गई होती।

भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए हम उक्त नियमावली के अनुबंध - II (IV) के अनुसार ऐसे संकेतकों पर विचार कर सकते हैं जो उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालते हों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा स्टॉक, लाभप्रदता निवल बिक्री प्राप्ति पाटन की मात्रा एवं मार्जिन इत्यादि।

क्षति के खतरे के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली में निम्नानुसार व्याख्या की गई है:

वास्तविक क्षति के खतरे का निर्धारण तथ्यों के आधार पर किया जाएगा और न कि केवल आरोप, कल्पना अथवा परोक्ष संभावना के आधार पर। परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऐसी किसी स्थिति का स्पष्ट तौर पर अनुमान लगाया जाना चाहिए और ऐसी स्थिति आसन्नवर्ती होनी चाहिए जिसमें पाटन से क्षति पहुंचेगी। वास्तविक क्षति के खतरे की मौजूदगी के संबंध में आकलन करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारकों पर विचार करेंगे:-

(क) भारत में पाटित आयातों की अत्याधिक वृद्धि दर जिससे आयातों में पर्याप्त वृद्धि की संभावना प्रदर्शित होती हो;

(ख) किसी अतिरिक्त निर्यात को खपाने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए निर्यातक की पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमता अथवा उसमें तत्काल पर्याप्त वृद्धि, जिससे भारतीय बाजार को अत्याधिक संवर्धित पाटित निर्यातों की संभावना प्रदर्शित हों;

(ग) क्या आयात ऐसी कीमतों पर हो रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर अत्याधिक न्यूनकारी अथवा हासकारी प्रभाव पड़ेगा और जिससे आगे और आयातों की संभावना बढ़ेगी; और

(घ) वस्तु की भण्डारगत स्थिति की जांच की जा रही हो ।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी घरेलू उत्पादकों के मामले में निम्नांकित आर्थिक मानदण्डों को नोट करते हैं तथा उनका अवलोकन करते हैं -

1. क्षमता एवं घरेलू बिक्री :

घरेलू उद्योग ने 1999 और 2002 के बीच अपनी क्षमता 5.00 लाख टन से बढ़ाकर 11 लाख टन अर्थात् लगभग 220% की वृद्धि कर ली है । तथापि, क्षमता में इस वृद्धि का मुख्य कारण चीन से पाटित आयातों, जिससे उद्योग को क्षति हो रही थी, पर पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने के बाद उद्योग की स्थिति में सुधार होना है । तथापि, इसी अवधि के दौरान क्षमता उपयोग **** से ***% के मध्य रहा है जिसमें 2001-2002 के दौरान मामूली वृद्धि हुई है । कुल मांग इसी अवधि के दौरान **** मी. टन, लगभग 16% बढ़ी है और घरेलू उद्योग का हिस्सा लगभग 13% से 26% बढ़ा है । तथापि, जहां घरेलू क्षमता कुल मांग की 37% हैं वहीं इसका बाजार हिस्सा 26% से कम रहा है ।

2. संबद्ध देश से आयातों में वृद्धि:

संबद्ध देशों से आयातों का हिस्सा कुल आयातों की तुलना में 2000-2001 में ***** से अत्याधिक बढ़कर जांच अवधि में ***** हो गया है और इसी अवधि के दौरान इस देश से आयातों का बाजार हिस्सा ***** से बढ़कर ***** हो गया है । बढ़ा हुआ आयात और बाजार

हिस्सा, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत में गिरावट, 4303/- रुपए मी.टन से घटकर इसी अवधि में 4188/- रुपए प्रति मी. टन हो गया, के अनुरूप है ।

3. कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री:

संबद्ध देशों से भारतीय बाजार में आयात ऐसी कीमतों पर हुए हैं जो कि इसके सामान्य मूल्य और घरेलू उद्योग के क्षतिरहित मूल्य से कम है और जिस घरेलू कीमत पर संबद्ध वस्तु को उत्पादित कर बेचा जा सकता है तथा अपने निवेश पर तर्कसंगत आय प्राप्त हो सकती है । घरेलू उद्योग की 1999-2000 की कीमत, इकाई कीमत प्राप्ति की तुलना में जांच अवधि में घटकर 95.5% रह गई थी । घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत *****/रु. प्रति मी.टन परिकलित की गई है, जबकि घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत जांच अवधि के दौरान *****/रु. प्रति मी. टन थी जिससे ***% तक की कम कीमत पर बिक्री हुई थी । अतः जांच अवधि में निवल बिक्री प्राप्ति रहित कीमत से कम रही है जिससे वित्तीय घाटा हुआ है ।

4. लाभप्रदता

1999-2000 की तुलना में संबद्ध वस्तु की कुल बिक्री मूल्य बढ़कर 213% हो गया था, लेकिन बनाने और बेचने की लागत भी इसी अवधि में 302% तक बढ़ गई थी । इससे यह संकेत मिलता है कि घरेलू उद्योग व्यापार में बने रहने के लिए अलाभकारी स्तर पर बिक्री कर रहा था और कीमतों के इस स्तर पर निवेश अलाभदायक था ।

5. निवेश पर आय एवं नकदी प्रवाह

घरेलू उद्योग के द्वारा निवेश पर आय जांच अवधि के दौरान नकारात्मक रही है और नकदी प्रवाह पर्याप्ततः प्रभावित हुआ है ।

6. निवल बिक्री प्राप्ति

1999-00 में निवल बिक्री प्राप्ति **** रु. प्रति मीट्रीक टन रही है जो 2000-01 में घटकर **** रुपए प्रति मी. टन तक की मामूली वृद्धि हुई है ।

7. घरेलू उद्योग के लिए मांग और वृद्धि की संभावना

संबद्ध वस्तु की मांग 1999-2000 से 2001-2002 में बढ़कर लगभग 16% हो गई है । इसलिए, घरेलू उद्योग को हुई क्षति के लिए मांग एक कारक नहीं रही है । किंतु संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण एक विचारणीय अवधि के लिए निवेश पर नकारात्मक आय घरेलू उद्योग की वृद्धि को धीमा कर रही है, यद्यपि वृद्धि के लिए अत्याधिक अवसर हैं जैसा कि पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई वृद्धि से देखा जा सकता है जब चीन से पाटित आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी सुरक्षा उपलब्ध थी ।

8. घरेलू उद्योग की माल-सूची

घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान अपनी मालसूची की स्थिति में सुधार किया है और इसलिए यह घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाला एक कारक नहीं है ।

9. रोजगार और मजदूरी

क्षमता में वृद्धि के कारण रोजगार में वृद्धि हो रही है । श्रम कानूनों के कारण बाज़ार दशाओं के द्वारा मजदूरी प्रभावित नहीं हो रही है । इसलिए इन कारकों को घरेलू उद्योग को क्षति के लिए अंशदायी नहीं माना जा सकता है ।

10. पाटन और क्षति की मात्रा

पाटन मार्जिन जिसे निर्यात कीमत का ----% परिकलित किया गया है संबद्ध देश से सभी निर्यातकों के लिए महत्वपूर्ण रूप से अधिक है क्षति मार्जिन को घरेलू उद्योग के लिए अनंतिम क्षति रहित कीमत, जिसकी गणना घरेलू उत्पादकों के लागत संबंधी आंकड़ों के आधार पर की गई है, के बीच अंतर के रूप में परिकलित किया गया है जो इस प्रकार है

(क) जे.एफ.ई. स्टील कार्पोरेशन

क्षति रहित कीमत: ***** रु. ***** अमेरिकी डालर

(विनिमय दर *****)

आयातों का पहुंच मूल्य: ***** अमेरिकी डालर

क्षति मार्जिन ***** अमेरिकी डालर

सी.आई.एफ. के % के रुप में क्षति मार्जिन 24.55%

(ख) मित्सुबिसी कार्पोरेशन

क्षति रहित कीमत: ***** रु. ***** अमेरिकी डालर

(विनिमय दर *****)

आयातों का पहुंच मूल्य: ***** अमेरिकी डालर

क्षति मार्जिन ***** अमेरिकी डालर

सी.आई.एफ. के % के रुप में क्षति मार्जिन 18.25%

(ग) अन्य

क्षति रहित कीमत: ***** रु. ***** अमेरिकी डालर

(विनिमय दर *****)

आयातों का पहुंच मूल्य:

***** अमेरिकी डालर

क्षति मार्जिन

***** अमेरिकी डालर

सी.आई.एफ. के % के रूप में क्षति मार्जिन 28.57%

11. निर्यातकों की क्षमता

प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि निर्यातक मै. जेएफई स्टील कॉर्पोरेशन की क्षमा उस देश में उपलब्ध मांग और भारत में कुल बाजार मांग की तुलना में बहुत अधिक है। इसलिए संबद्ध देश से पाटित संबद्ध वस्तु की मात्रा, जिससे कीमतों में हास हो रहा है, घरेलू उद्योग को क्षति का एक आसन्न खतरा है। ऐसी पाटित कीमतों के परिप्रेक्ष्य में घरेलू उत्पादक घरेलू विग्रय कीमत को एक यथोचित स्तर पर बनाए रखने में असमर्थ होंगे जोकि अन्यथा उन्हें उपलब्ध होतीं, यदि इस तरह पाटन न हुआ होता।

प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि निर्यातक मै जे एफ ई स्टील कॉर्पोरेशन चीन से अच्छी गुणवत्ता का कैटकोक इसके खुद के उपभोग के लिए आयात करते हैं तथा अपने कोक चूल्हों / ओवनों से प्राप्त बेशी कोक जिसे ये अपने ब्लास्ट फर्नेसों में उपयोग नहीं कर सकते उसे पाटित कीमतों पर भारत को निर्यात कर दिया जाता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोक ओवन में मैटकोक के विभिन्न आकारों का उत्पादन एक सामान्य घटना है और चीन से आयातों के द्वारा अपनी निजी जरूरतों की पूर्ति के द्वारा निर्यातक इस स्थिति में हैं कि वह भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन जारी रख सके। इसलिए वर्तमान उपलब्ध क्षमता और हाल के पाटित आयातों से हुई कीमत कटौती को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह मानते हैं कि जापान के निर्यातक भारत में संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादकों को वास्तविक क्षति पहुंचा रहे हैं और उन्हें आगे भी वास्तविक क्षति पहुंचने का खतरा है।

कारणात्मक संबंध

ऊपर दिए गए सभी विवेचित कारकों का परीक्षण करने के पश्चात प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह मानते हैं कि संबद्ध देश से पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति

पहुँचाई है और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के लिए कोई अन्य कारक उत्तरदायी नहीं है । इसके अलावा घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से जारी पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति का खतरा है क्योंकि संबद्ध देश में निर्यातक के पास पाटन जारी रखने के लिए पर्याप्त क्षमता है । पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की संभावित वृद्धि और स्थापना भी प्रभावित हो रही है ।

7. भारतीय उद्योग का हित और अन्य विषय

प्राधिकारी का यह भी विचार है कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य साधारणतया पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षतियों को दूर करना है ताकि भारतीय बाजार में एक खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति की बहीली हो सके, जो बात देश के आम हित में है ।

प्राधिकारी इस बात को भी मानते हैं कि यद्यपि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध वस्तु के उपयोग से विनिर्मित उत्पाद का मूल्य स्तर प्रभावित हो सकता है और परिणामस्वरूप यह इन उत्पादनों की तुलनात्मक प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ असर डाल सकता है, तथापि, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा इन पाटनरोधी उपायों से कम नहीं हो पाएगी । इसके विपरीत, पाटनरोधी उपाय को लागू करने से पाटन की पद्धतियों द्वारा अर्जित अनुचित लाभ को दूर किया जा सकेगा और इससे घरेलू उद्योग का ह्रास रुकेगा और उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तु के व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी । पाटनरोधी उपायों से संबद्ध देशों से होने वाले आयात किसी भी तरह से कम नहीं होंगे और इस प्रकार उपभोक्ताओं के लिए इन उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी ।

8. पहुँच मूल्य

इस उद्देश्य के लिए आयातों का पहुँच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अधीन सीमाशुल्क विभाग द्वारा यथा निर्धारित आंकलन योग्य मूल्य होगा और उसमें सीमाशुल्क

अधिनियम 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर, सभी प्रकार के शुल्क शामिल होंगे ।

(घ) निष्कर्ष :

प्राधिकारी शामिल मुद्दों और हितबद्ध पक्षकारों की दलीलों की जांच करने के बाद अनंतिम रूप से यह मानते हैं कि :

(क) संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं को सभी रूपों में भारत को इनके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया है ।

(ख) घरेलू उद्योग को पाटित संबद्ध वस्तु की कम पहुंच कीमत के कारण कीमत में कमी के चलते घटी हुई निवल विक्री प्राप्तियों (एन एस आर) के कारण वित्तीय घाटे के रूप में वास्तविक क्षति भी उठानी पड़ी है ।

(ग) घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन द्वारा क्षति पहुंचाई गई है ।

(घ) प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित अध्याय 27 के अंतर्गत आने वाली संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ।

(ङ) पाटनरोधी शुल्क की राशि को पाटन मार्जिन के समान करने की सिफारिश पर विचार किया गया ताकि घरेलू उद्योग को पाटन के कारण हो वाली क्षति को दूर किया जा सके । तदनुसार यह सिफारिश की जाती है कि सीमाशुल्क के अध्याय 27, उप-शीर्ष 270400 के अंतर्गत आने वाले संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर अंतिम निर्धारण होने तक केन्द्र सरकार द्वारा जारी की जा वाली तत्संबंधी अधिसूचना की तरीख से लगाया जाए ।

आगे की प्रक्रिया:-

प्राथमिक जांच परिणामों को अधिसूचित कर दिये जाने के बाद निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी ।

(क) प्राधिकारी इन जांच परिणामों पर सभी हितबद्ध पक्षकारों के विचार आमंत्रित करते हैं जिन पर अंतिम जांच परिणामों के लिए विचार किया जाएगा ।

(ख) संबंधित ज्ञात निर्यातकों, आयातकों, याचिकाकर्ता और अन्य हितबद्ध पार्टियों को प्राधिकारी द्वारा अलग से पत्र लिखकर अपने विचार, पत्र जारी होने की तारीख से चालीस दिन के भीतर भेजने को कहा जा रहा है । कोई अन्य हितबद्ध पार्टी भी इन जांच परिणामों के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिन के भीतर अपने विचारों से अवगत करा सकती है ।

(ग) जहां तक आवश्यक समझा जायेगा प्राधिकारी सत्यापन भी करेंगे ।

(घ) प्राधिकारी सभी हितबद्ध पार्टियों को मौखिक सुनवाई का भी अवसर प्रदान करेंगे जिसके लिए तारीख और समय की सूचना ज्ञात हितबद्ध पार्टियों को अलग से दी जायेगी ।

(ङ) प्राधिकारी अंतिम जांच परिणाम घोषित करने से पूर्व आवश्यक तथ्यों को प्रकट करेंगे ।

एल. वी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

परिशिष्ट-

क्र. सं.	उप शीर्ष या टैरिफ मद	माल का विवरण	विनिर्देशन	उदगम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्गतक	राशि	माप की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	२७०४००	कम ऐश वाला मेटलर्जिकल कोक, जिसमें ऐश की मात्रा १५ प्रतिशत से कम है फरो अलाय उत्पादन के लिए आवश्यक ०.०१६६ प्रतिशत से कम वाले फास्फोरस से अन्य	शून्य	जापान	कोई देश	कोई उत्पादक	कोई निर्यातक	११८.४४	मी. टन	अमरिकी डालर
2.	२७०४००	कम ऐश वाला मेटलर्जिकल कोक, जिसमें ऐश की मात्रा १५ प्रतिशतसे कम है फरो अलाय उत्पादन के लिए आवश्यक ०.०१६६ प्रतिशत से कम वाले फास्फोरस से अन्य	शून्य	कोई देश	जापान	कोई उत्पादक	कोई निर्यातक	११८.४४	मी. टन	अमरिकी डालर

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)
NOTIFICATION
New Delhi, the 14th October, 2003
PRELIMINARY FINDINGS

Sub : Anti-Dumping Investigation concerning imports of Metallurgical Coke originating in or imported from Japan

No. 14/41/2002-DGAD.— Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof:

A. PROCEDURE

1. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:
 - i) The Designated Authority (hereinafter also referred to as Authority), under the above Rules, received a written application from Indian Metallurgical Coke Manufacturer's Association (IMCOMA), (hereinafter referred to as petitioner) on behalf of domestic industry, alleging dumping of Metallurgical Coke (Metcoke, hereinafter also referred to as subject goods) originating in or exported from Japan. The following domestic producers of Metallurgical Coke are party to this petition:

M/s BLA Industries Ltd., Mumbai
M/s Durgapur Project Ltd., Kolkatta
M/s Antai Balaji Coke Ltd., Kolkatta
M/s Saurashtra Fuels Pvt. Ltd., Mumbai
M/s Southern Fuels Ltd., Bangalore
M/s Sesa Kembla Coke Co. Ltd.
 - ii) The petition is also supported by M/s Gujarat NRE Coke Ltd., Kolkatta.
 - iii) Preliminary scrutiny of the application filed by the petitioner revealed certain deficiencies, which were subsequently rectified by the petitioner. The petition was, therefore, considered as properly documented.
 - iv) The Authority on the basis of sufficient evidence submitted by the petitioner decided to initiate the investigation against imports of subject goods from Japan. The authority notified the Embassy of Japan in New Delhi about the receipt of dumping allegation before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-Rule 5(5) of the Antidumping Rules.

- v) The Authority issued a public notice dated 20th March, 2003 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating Anti-Dumping investigations concerning imports of Metallurgical Coke classified under custom Code 27.04 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975 and under ITC HS Classification Rule 2704.00, originating in or exported from Japan (hereinafter referred to as subject country).
- vi) The Authority forwarded copies of the public notice to the known exporters (whose details were made available by petitioner) and gave them an opportunity to make their views known in writing within forty days from the date of the letter in accordance with Rule 6(2) supra.
- vii) The Authority sent a questionnaire to elicit relevant information to the following known exporters/producers, in accordance with the Rule 6(4):
 - 1. M/s Mitsubishi Corporation, Tokyo, Japan
 - 2. M/s Sumitomo Corporation, Tokyo, Japan
- viii) The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known importers (whose details were made available by petitioner) of subject goods in India and advised them to make their views known in writing within forty days from the date of issue of the letter in accordance with Rule 6(2).
- ix) Request was made to the Central Board of Excise and Customs (CBEC) to arrange details of imports of subject goods made in India during the past three years, including the period of investigation.
- x) The Embassy of the subject country in New Delhi was informed about the initiation of the investigation in accordance with Rule 6(2) with a request to advise all concerned exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time. A copy of the letter, petition and questionnaire sent to the known exporter was also sent to the Embassy of the subject country in accordance with Rule 6(3). A copy of the non-confidential petition was also provided to other interested parties, wherever requested.
- xi) A questionnaire was sent to the following known importers/user-associations of the subject goods for necessary information in accordance with Rule 6(4):
 - i) M/s Gujarat Heavy Chemicals Ltd., Ahmedabad, Gujarat
 - ii) M/s Jayaswal Neco Ltd., Kolkata
 - iii) M/s Southern Iron & Steel Co., Coimbatore, Tamil Nadu
 - iv) M/s Sathavahan Ispat Ltd., Hyderabad
 - v) M/s Kirloskar Ferrous Industries, Pune
 - vi) M/s Unimetal Ispat Ltd., Secunderabad
 - vii) M/s Malvika Steel Ltd., Sultanpur
 - viii) M/s Lanco Industries Ltd., Secunderabad

- ix) M/s Tisco Ltd., Bombay
 - x) M/s Vishveseraya Iron & Steel, Bhadravati, Karnataka
 - xi) M/s Unimetal Alloys Ltd., Secunderabad
 - xii) M/s Gujarat Heavy Chemicals, Ahmedabad, Gujarat
 - xiii) M/s Association of Indian Mini Blast Furnaces, New Delhi
 - xiv) M/s Indian Ferro Alloy Producers Association, Mumbai
- xii) Various interested parties requested for extension of time for filing their responses to the Initiation notification. Accordingly, extension was granted to all the interested parties upto 15th May, 2003.
- xiii) Response/information to the questionnaire/notification was filed by the following exporters/producers:-

1. M/s Mitsubishi Corporation, Japan
2. M/s JFE Steel Corporation, Japan

M/s Sumitomo Corporation, Tokyo, Japan, the company originally named in the petition, also responded to the initiation notice and has informed that they did not export any Met Coke from Japan to India during 1st April 2001 to June 2002. However, M/s JFE Steel Corporation, Japan, who is the actual producer of the subject goods in the subject country has filed a response *suo moto* and has agreed to co-operate in the investigation. Two major producers of Metcoke in Japan i.e., M/s NKK Corporation and M/s Kawasaki Steel have merged to form new corporation called M/s JFE Steel Corporation w.e.f. 1st April 2003.

xiv) Response/information to the questionnaire/notification was filed by the following importers/user Associations.

1. M/s Indian Ferro Alloys Producers Association, Kolkata
2. M/s Association of Indian Mini-blast Furnaces
3. M/s Electrosteel Castings Ltd.
4. M/s Aparant Iron & Steel Pvt. Ltd.,
5. M/s Hindustan Zinc Ltd
6. M/s Saurashtra Chemicals Ltd.
7. M/s Fairdeal Suppliers Pvt. Ltd.,
8. M/s Jayaswal Neco Ltd
9. M/s Usha Beltron Ltd
10. M/s Ispat Metalics India Ltd.
11. M/s TISCO
12. M/s Kalyani Ferrous India Ltd.
13. M/s Kirloskar Ferrous Industries Ltd.
14. M/s Usha Ispat Ltd.

xv) The Authority kept available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file maintained for this purpose and kept it open for inspection by the interested parties as per Rule 6(7).

xvi) The Authority conducted on-the-spot investigation at the premises of the petitioners to the extent possible. Cost investigation was also conducted to work out optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and the information furnished by the petitioner.

xvii) On the request of various interested parties, the Authority held a public hearing to understand various issues raised by the parties and the written submissions made after the hearing and rejoinders thereof have been incorporated into this finding.

xviii) ****in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

xvii) Investigation was carried out for the period starting from 1st April 2001 to 30th June 2002 i.e. the period of investigation (POI).

B. VIEWS OF EXPORTERS, IMPORTERS AND OTHER INTERESTED PARTIES

1. PETITIONER'S VIEWS

a) PRODUCT UNDER CONSIDERATION

The product for which this petition has been filed is Metallurgical Coke (Metcoke) with an ash content of less than 18% (eighteen percent) which is being dumped in the Indian market by the exporters from Japan. The petitioner have contended that the subject Metcoke imported from Japan uses coking coal having ash content of less than 13% and therefore Subject Metcoke of only up to 18% is being imported into India.

The petitioners contend that coal having high ash content is primarily found in the Indian subcontinent. Whereas, the imported subject Metcoke is manufactured from low ash content coal and, therefore, would not exceed 18% in ash content. Subject Metcoke is produced by destructive distillation of Metallurgical coking coal in the absence of oxygen at high temperature, generally ranging around 1000 degrees centigrade, without burning the coal.

The properties of the resultant Subject Metcoke are directly dependent on the input of the coal. Any Metcoke comprising of ash content of less than 18% would require coal input having a natural ash content of less than 13% for which the coal is imported. Indian coal generally has a natural ash content in excess of 20%.

Metcoke produced is mainly carbon along with some mineral and residual volatile material. Metcoke is used as a primary fuel in industries where a uniform and high temperature is required in kilns or furnaces.

Metcoke is classified under chapter 27 (under sub-heading 27.04) of the Customs Tariff Act, 1975. The classification, manufacturing process and usage of the product indicated herein are, however, indicative only and are in no way binding on the scope of the product under consideration.

Metcoke (including Subject Metcoke) is used in various industries including pig iron, foundries, ferro alloys, chemical, integrated steel plants and others.

Given that the product under consideration is Subject Metcoke having an ash content of less than 18%, the producers of Subject Metcoke having an ash content of above 18% are excluded by the petitioners from their petition.

b. Like Product

The petitioners contend that there is no noticeable difference in the imported product and the petitioners' products. The subject Metcoke produced by the petitioners in India is directly interchangeable with imported subject Metcoke from Japan.

c. INDIAN INDUSTRY PROFILE

The producers of Subject Metcoke in India may be broadly categorized in three groups. First, those who are primarily integrated steel plants such as TISCO, Rashtriya Ispat Nigam Limited and SAIL who captively consume the Subject Metcoke they produce, as well as resort to large scale imports from other countries including Japan. Second, stand-alone Subject Metcoke producers who produce Subject Metcoke from imported Low Ash Coal, and third, stand-alone small scale sector producers located in Bihar, Bengal and Jharkhand, who are represented by Industries and Commerce Association (ICA). The latter generally uses Indian coal to produce Metcoke and by and large produces Metcoke having an ash content of above 18%.

The Designated Authority had in the earlier case, involving Metcoke from China, for the purposes of demarcating Domestic Industry, excluded those producers who captively produce and consume the product under consideration. This fact was confirmed by the Hon'ble CEGAT. To the best of the Petitioners knowledge no producer produces Metcoke with an ash content of less than 18% for captive consumption. In any event, these captive consumers should be excluded in keeping with the decision of the Hon'ble Designated Authority and the Hon'ble CEGAT.

d. PRODUCTION PROCESS

In the coke-making processes, bituminous coal, containing Volatile Matter (VM), is fed, usually after processing operations to control the size and quality of the feed, into a series of ovens which are sealed and heated at high temperatures in the absence of oxygen, typically in cycles lasting 14 to 36 hours depending upon the quality of coal and its VM content. There are primarily two kinds of Processes to Manufacture Metcoke:

Non Recovery Process

In the Non Recovery Process, Volatile compounds that are driven off the coal due to heating are fully combusted inside the ovens and the solid carbon remaining in the oven is coke. It is taken to the quench tower, where it is cooled with a water spray or by circulating an inert gas (nitrogen), a process known as dry quenching. The coke is screened into different sizes and sent to a blast furnace or to storage.

Byproduct Recovery Process

In the By-product Recovery Process, Volatile Matter is collected. Coke oven gas is cooled and by-products are recovered. Flushing liquor, formed from the cooling of coke oven gas and liquor from primary coolers contain tar and are sent to a tar decanter. An electrostatic precipitator is used to remove more tar from coke oven gas. The tar is then sent to storage. Ammonia liquor is also separated from the tar decanter and sent to waste water treatment after ammonia recovery. Coke oven gas is further cooled in a final cooler. Naphthalene is removed in the separator on the final cooler. Light oil is then removed from the coke oven gas and is fractionated to recover benzene, toluene and xylene. Some facilities may include an onsite tar distillation unit. The Claus process is normally used to recover sulfur from coke oven gas. The coke oven gas is also directly used as fuel in power plants and for heating after stripping it of noxious elements. The recovery value of the coke oven gas generally depends upon its calorific value and volume of recovery in standard cubic meters.

Among the petitioners and their supporters, only M/s Durgapur Projects employ the Recovery Process. Based on the actual experience of M/s Durgapur Projects Ltd., the recovery is approximately **% of the cost of manufacturing coke.

The petitioners also contend and emphasize that the capital cost of installing a recovery coke over plant is significantly higher than the cost of a non-recovery plant and therefore actual recovery gain is much less taking capital cost into account.

During the coke quenching, handling and screening operation, coke breeze is produced. It is either reused on site (e.g. in the sinter plant) or sold off site as a by-product. This is under both processes.

e. Users of Metcoke

Iron Foundries: Iron Foundries use coke in the Cupola to melt iron for casting it into various shapes as per application. The iron foundries in India are spread out throughout the country.

Steel Foundries: Steel foundries use coke to provide additional carbon content to the molten metal depending upon the specification of the casting.

Non ferrous metal castings; Foundries that make castings of Copper and Brass use Coke for melting the metal.

Lead and zinc Smelters: Coke is a prime ingredient in the process of lead and Zinc smelting.

Secondary Steel Producers: 'Mini' steel plants that produce steel from recycled steel scrap and sponge irons require coke.

Chemical Plants; Some soda ash plants and calcium carbide producers require coke in their process.

Ferro Alloy Plants: Ferro alloy producers require coke for their production. Coke is used as a reducing agent in this process.

Pig Iron Producers: Production of pig iron requires coke. In India small pig iron producers require coke and buy the coke from the open market. Typically larger steel producers have their own plants and therefore, are not in the market to buy coke.

f. Import of Metcoke

Import of Subject Metcoke 1999-2002

	Japan	Other countries	Total
1999-2000			
Quantity In MT	329472	1989931	2319403
Value in Rupees	1119654298	6793571892	7913236690
Rate Rs/PMT	3398	3414	3412
2000-2001			
Quantity In MT	200309	2184129	2384438
Value in Rupees	86190399	8187752510	9849655809
Rate Rs/PMT	4303	4115	4131
2001-2002			
Quantity In MT	371018	1912991	2284009
Value in Rupees	1494552853	7670211501	9170764354
Rate Rs/PMT	4028	4013	4015

Imports from other countries except Russia and China are de minimis and therefore not being considered as being dumped in India. Imports from China, which is about 50.51% of total imports, are subject to antidumping duty since 1998.

f. Dumping and Normal value

The petitioners claim that in the absence of any useful information, besides the cost of coal, in the public domain they have not been able to get the selling price of the subject Metcoke in the domestic market of the exporting country. Accordingly, they have constructed the normal value of the subject Metcoke as Rs***** based on the international price of coal imported by Japan from Australia, China and Canada and costs from Indian manufacturers using the recovery and non-recovery processes with appropriate modifications.

Estimates of Export Price

The Export Price for the subject goods from Japan has been worked out on the basis of the import figures of the DGCI&S. Since the DGCI&S figures are on CIF basis, adjustments towards ocean freight, Marine insurance, Inland transport charges, Port handling charges in Japan, trading house commissions have been made.

The adjusted ex-factory export price after the above adjustments has been worked out by the petitioners as Rs*****.

On the basis of the above constructed normal value and export price the petitioners have indicated the Dumping margin as 64.06%, both in terms of Rupee and Dollar.

g. Injury

The petitioners contend that margin of dumping from, the subject country is more than the 2% limit expressed as % of export price. Also the volume of import from the subject country is more than the de-minimis.

The petitioners also contend that the domestic industry is suffering material injury on account of dumping as would be revealed from various economic and financial parameters discussed as follows:

- The industry was relieved after imposition of antidumping duty on imports of subject Metcoke from China in 1998 and drew up a plan of capacity expansion. However the dumped imports from Japan are creating fresh problems for the industry.
- That the imports from the subject country in comparison to the total imports have increased substantially from 8.40 % in 2000-2001 to 22.62% during the period of investigation.

Year	Imports from Subject Country (MT)	Total Imports	% share
1999-2000	329472.00	2319403.00	14.21%
2000-2001	200309.00	2384438.00	8.40%
POI	660753.00	2921303.00	22.62%

Source: DGCI&S

- Further, imports from the subject country, in comparison to the total demand in the country, have also increased from 6.49% in 2000-2001 to 20.28% during the period of investigation.
- That as against an average price of Rs. 4303/- per MT in the year 2000-2001, the imports from subject country for the period of investigation came at an average price of Rs. 4188/- per MT.
- That though the domestic industry has increased the capacity during the POI by about 328% over 1999-2000, the increase in the market share of the domestic industry has to be viewed in the context of the addition of the new capacity in the country. The demand has also grown from 26,88,499 MT in 1999-2000 to 32,58,344 during the POI.
- The complainant domestic industry tried its best to hold on to the customers. Yet the fact that 6,60,753 MT of dumped imports arrived into India during POI is adequate evidence that it lost potential customers.
- It may be seen that the production by the petitioners in quantitative terms went up during the period of investigation over the preceding financial year. However this is essentially because of increase in capacity of the domestic industry. After the imposition of duty from China, domestic industry was on the road to recover, however dumping from Japan and subsequently resumption of dumping from China have thwarted these efforts.
- That despite increased production in quantitative terms there has been a marginal increase in the capacity utilization of the domestic industry to the extent of about ***% in the period of investigation over the preceding financial year.
- Though the volume of sales by the petitioners went up during the period of investigation over the preceding financial year, the industry is not realizing the price in the period of investigation as against the price in 1999-2000. Because of the pressure on prices from imports from subject country, the domestic industry is not able to realize a fair price or a reasonable rate of return, as would be seen from the table below:

Year	Sales Volume (MT)	Sales value (Rs. In lakhs)	Unit price (Rs./MT)
1999-2000	100.00*	100.00*	100.00*
2000-2001	213.81*	192.41*	89.99*
2001-2002	328.40*	313.59*	95.49*

* Indexed Figure

- **Inventories:-** The inventories of the Petitioners have decreased from ***** MT at the end of March 2001 to **** MT as on 31.03.2002.
- **Employment:-** Due to increased capacity of the domestic industry, there has been an increase in the employment. Thus, injury to the domestic industry cannot be judged on the basis of employment.
- **Wages:-** No impact on wages as wages are determined according to the Labour Laws. The wages cannot be changed according to the financial health of the petitioner companies.
- **Profitability:-** To retain its market share, the Domestic Industry had no option but to reduce its price to unremunerative levels.
- **Return on Investment (Capital Employed):-** As enumerated above the industry is operating at a loss and thus the domestic industry has not been able to earn any return on its investments.
- **Price Underselling:-** The landed value of the product under consideration from Japan (Rs4397) is much lower than the prices the domestic industry ought to have realized on the sales of the subject goods. The injurious effect of this high level of price underselling has had a direct and deleterious effect on the financial performance of the domestic industry.

		Japan
1.	Desirable Selling Price of Domestic Industry (Excluding Excise Duty)	***
2.	Landed Value of Imported product	4397
3.	Extent of Underselling	***
4.	% of Underselling (3/1)	***

Based on 31.03.2002 Figures

- **Price Undercutting:-** The effect of the injury to the domestic industry due to dumped imports is further accentuated by the fact that not only the subject goods are being undersold, the exporters from the subject country are also indulging in price undercutting. The landed value (i.e., the CIF price plus customs duty) of the dumped imports has been much below the selling price of the domestic industry during the period of investigation. Thus there is a constant pressure on the domestic industry to bring down their prices lower than even the current prices, which are not at all remunerative.

- That the domestic industry has not been able to earn even nominal returns on the capital employed. Hence, there is a considerable impact on cash flows coupled with the fact that the inventory levels in this industry are quite high.
- That due to the nominal returns in the industry and continued dumped imports, the domestic industry is not in a position to grow in the national interest despite the fact that it is meeting only a small portion of the domestic demand.

C. Views of exporters, Importers and other interested parties

1. Exporter's views:

i) Period of investigation

The period of investigation (POI) considered by the Designated Authority in the present investigations is unsupported by the guidelines issued by the Designated Authority as also practice being followed by the Designated Authority in India and other Investigating Authorities world over, on, inter-alia, the following grounds: -

- Guidelines issued by the Designated Authority provide that investigation period should be as recent as possible. The period considered in this case is not as recent as possible at the time of initiation.
- Investigation period fixed in Other Cases was much more recent than this case.
- Designated Authority has in fact directed the domestic Industry (in other cases) to update the petition when it is found that the period in the petition is quite old and the data may be stale.
- There is a significant increase in the prices of the Metcoke after the close of the present investigation period. At the same time, the cost of production has largely remained in the similar band. This is due to a very major change in the Metcoke market dynamics. The petitioner has quietly suppressed the fact from the Designated Authority before initiation of investigations only to perhaps allege subsequently during the course of the investigations that this changed scenario is a post investigation period phenomenon.
- Availability of data/information does not support the period fixed. On the date of initiation, data in respect of imports had become available at least till Oct 2002. Further, it is understood that it is the practice of the Directorate to extend the investigation period to three months beyond the period in the petition in case it is found that the period in the petition is old and stale.
- Respondent exporters understand that the Designated Authority has very recently recognized that vital post POI factors cannot be ignored, provided that they may have significant impact on the entire case. In the instant case, increase in the prices to a level of US\$140-150 per metric ton (FOB), when the prices in the POI were in the region of US \$ 90-100 per metric ton, is a very vital fact which cannot be ignored, more so when the petitioner has deliberately chosen a very old

POI. It should be noted in this regard that increase in the prices of the Metcoke is universal and significant. This price increase, having been triggered due to closure of plants in the China, is not temporary in nature.

ii) Standing of the domestic Industry:

The respondent exporters contend that the standing requirement has not been satisfied as the manufacturing capacities of the captive producers and small-scale producers in Bihar, Bengal and Jharkhand (represented by the Industry and Commerce association-ICA) have not been taken into account. They argue that the petition contains a lot of conjectures with regard to production by various producers and no evidence has been presented. There is no evidence in the petition that ICA members produce the Metcoke with above 18% ash content. In fact, they produce the Metcoke with ash content of below 18%. Further, there was no evidence in the petition with regard to imports by certain parties. The petitioner has excluded captive producers referring to the finding of the Designated Authority in the matter concerning Metcoke from China as well as CEGAT decision. However, as held by the WTO in the matter of United States: Hot Rolled Steel Products from Japan, merely because some company consumed the material for captive purposes, such production can not be excluded.

The petitioner has excluded production by some producers on the grounds that they produce for captive purposes only. However, Rule 5(3) read along with other relevant Rules make no distinction with regard to captive production and merchant production. With the amendment in definition of Rule 2(b), exclusion of a producer related to importer or a producer himself importing is not automatic. There should be sufficient grounds for such exclusion. Further, such an exclusion can only be done by the Designated Authority and not by the petitioner.

iii) Product under consideration:

The product under consideration in the investigation against China covered the Metcoke up to 15% ash content. In the present petition, the Metcoke up to 18% ash content has been considered. There is no reasoning or justification given in support of this extension of the product under consideration. Interestingly, at the same time, the petitioner has stated that the Metcoke being imported from Japan contains 13% ash content. It is not understood why the ash content of the Metcoke under consideration should be kept up to 18%, while the imported Metcoke has ash content of only up to 13%.

The exporters submit that the petitioner has not given complete description of the product involved. The following parameters describe the Metcoke: -

- a) Moisture;
- b) Ash;
- c) Size;
- d) Volatile Matter;
- e) Fixed Carbon;
- f) Sulphur;
- g) Phosphorus;

- h) M 40;
- i) M 10; and
- j) Ash fusion temp.

The petitioner has recognized only ash content as a parameter.

While the issue of Ash content and its criticality in the product and its use has already been recognized and settled by the Designated Authority, the issue of moisture content in the Metcoke and its relevance requires to be recognized.

“Moisture” in the Metcoke is an inevitable fact, from not only production but also sale point of view. At the same time, higher moisture content implies higher water in the material and lower quantity of the Metcoke. Thus, while the consumers would ideally like to buy the Metcoke with zero moisture content. However, certain minimum moisture content is inevitable in the product. So much is the relevance of moisture content that in case moisture content exceeds beyond the maximum limits, the producers have to pay penalties in terms of deductions from the sale value consideration.

iv) Dumping and Injury

- The export price to India must take into account the moisture content and generation of fines due to multiple handling. Exports of the Metcoke from Japan involve the following minimum handling: -
 1. Stacking after production;
 2. Loading of the material on ship at the loading port;
 3. Unloading of the material at discharging port;
 4. Shifting of the material from discharging port to the consumer's storage; and
 5. Shifting from storage to production department.

As against this, domestic sale of the material in Japan involves only 1, 4 and 5 steps. Thus, exports of the material involve at least two additional handling. Since the number of handling is more in case of exports, the generation of fines is resultantly higher. Export price to India or any other market must take this vital factor into account.

- That the Indian Producers can meet hardly 20% of the domestic Metcoke demand. This leaves the consumers with no option but to import, regardless of price. This fact is established by continued imports, even after payment of Anti Dumping Duty from China.
- That the cost of coal, the primary raw material for manufacturing coke has not undergone any significant change in last several years and that the production of Indian Producers have significantly increased over the last five years. Given these two favourable factors with the Indian Producers, it follows that the cost of production of metcoke should not have increased significantly for the Indian Producers.

- There are two processes for production of the Metcoke. These are (a) recovery type, and (b) non-recovery type. In a recovery type plant, coke oven gas, Coal Tar (and its derivatives like Pitch, Crude Benzene etc.) and Chemicals like Ammonia, Ammonium Sulphate etc., generated in the production process are recovered and used by the producers elsewhere (in steel making in an Integrated Steel Plant). However, a stand-alone producer of the Metcoke (who does not produce steel) can not use the coke oven gas to its fullest extent, even though recycling for own utilities requirement is feasible in a limited way. This vital difference in production technology between the Japanese producers and Indian Producers is resulting in huge difference in cost of production of the Metcoke. The exporters consider that Indian Producers are suffering due to this technological difference.
- In view of the foregoing the exporters contend that Mitsubishi Corporation or JFE Steel has not resorted to dumping of the material in India and exports made by MC and JFE have not and could not have caused injury to the Indian Producers, given that the imports were necessitated due to inability of the Indian Producers to supply the material. Prices of the Metcoke have very significantly increased and Indian Producers face no threat of injury.

2. Importers' and other interested parties' Views

Views of the importers and other interested parties are summarized as follows:

- That the Period of Investigation mentioned in the Initiation Notification does not reflect the true and fair picture because of the fact that there has been hardly any shipment from Japan since the last 9 months, and if at all any shipment has been effected they have been effected at exorbitant prices. The Domestic Industry has very conveniently chosen this period to misguide the authorities, to remove and negate any competition with the sole intention of large scale profiteering.
- The Chinese Met Coke forms over 75 to 80% of the total imports into India and imports from Japan form a tiny part in the total import of Metallurgical Coke into India. The Metallurgical Coke exported from Japan is mainly Steel Plant rejects and the size of the coke ranges between 20mm – 60mm. This very size restriction imposes a lot of limitations and can be used only by limited user industries.
- As against this, the Indian Manufacturers can generate only about 20 to 25% of its total production in this size range (20-60mm) in a normal production cycle, whatever be the process; either Recovery Type and/or Non-Recovery Type. For additional quantities, they need to use Disintegrators, which leads to dusting and greater breakage losses resulting in higher costs.
- Japan has only one dedicated cokery and it exports almost 90% of its produce to USA, Europe and South America. Other than the aforesaid cokery all the coke being exported from Japan including the alleged dumped imports are rejects of their integrated Steel Plants.

- The article under investigation has been fixed taking into account only one of the parameters of the chemical composition i.e., the ash content, whereas the Bureau of Indian Standards has prescribed 8 different types of physical and chemical properties that are to be tested if the coke can be considered as a Like Article.
- That the Domestic Industry which has almost doubled its production capacity since the imposition of Dollar Term Anti Dumping Duty on Imports of Metallurgical Coke from China, claim that there has been injury on account of Low price of imports from Japan. Losses to the industry on account of unremunerative selling price, price under selling, price under cutting, negative returns on capital employed are totally baseless and erroneous.
- That the benefits of the imposition of Anti Dumping Duty on Coke from China can be very well seen from the capacity expansion being made by the Domestic Industry. On the contrary, the user industry which is dependant on Low Ash Metallurgical Coke are being held to ransom by the Domestic Industry by having to pay exorbitant prices and dictated payment terms.
- The claim of the Domestic Industry that there is dumping of Coke from Japan, exported at prices below the Normal Value, is incorrect. It is well known that the International prices of Low Ash Metallurgical Coke has sky rocketed and the demand for the coke is in excess over the supply position.
- The Domestic Industry has tried to create an impression that the Coke Industry is reeling under the effect of Dumping, whereas in reality they are already earning hefty margins on the Coke being sold, and it is the User Industry which is being forced into increasing its input costs and in turn increasing their cost of production.
- That the average CIF value of imports of Metcoke from Japan during the POI was US\$*** (Rs****) PMT (@ the Exchange Rate of ****) and not Rs4188/- PMT as claimed by the petitioners.
- On the basis of the above average CIF value landed cost of imported Metcoke from Japan works out to Rs***** PMT. As against this, the average cost of manufacture for the Domestic Industries, inclusive of all expenses would be Rs**** PMT.
- In spite of the input costs being more, because of higher freight cost for import of coal compared to Indian manufacturers, the Japanese Manufacturers; based on better technology and efficient operations, can supply the material at competitive rates, in addition to higher quality.
- That the material so imported from Japan has been sold at prices above Rs. **** PMT during the POI and presently, the CIF cost itself is about US\$ *** PMT for the Subject Met Coke.

- It is clear from the above that the Japanese material is not used to under-cut the prices of the Local Manufacturers. On the contrary, the said Sales Price gives ample opportunity and leeway to the Domestic Industry for increasing their prices substantially, if so desired.
- That the coke manufactured by the Indian Metcoke manufacturers can not be treated as like product vis-a vis the Metcoke imported from Japan because of its characteristics in terms of other parameters like sulphur and Phos content, hardness, porosity, reactivity etc. which are very important factors from the point of view of the user industries' requirements. Because of the special characteristics of Japanese Metcoke it is used in specific industries and command higher price. Percentage of Ash alone cannot be a sole criterion for judging the two materials to be alike.
- That the cost of raw material, which is over 85% of the total cost of production, has been more or less stable for the past 3 to 4 years including the POI.
- That there is a tremendous growth in demand of Metcoke in the exporting countries themselves and in other importing countries and the demand far exceeding available supply, there can not be any dumping; going by the actual market scenario.

In addition to the above general views of the interested parties the Association of Indian Mini-blast furnaces and Indian Ferro Alloy Producers' Association has also made the following submissions:

Association of Indian Mini-blast furnaces:

- That the CIF price of Metcoke (with about 12.5% Ash content) has increased from US\$ 80 in October 2001 to over US\$ 145 in March 2003. At the present price level there is no injury to the domestic industry, especially when there is no significant change in price of low ash coal used for low ash metcoke manufacturing.
- In the present scenario of shortage of Metcoke world over there is no possibility of dumping by Japan or any other country.
- With a view to produce Pig Iron indigenously and to make secondary steel sector viable and competitive, the Government encouraged setting up of Mini Blast Furnaces leading to use of indigenous Iron ore and substantial saving of power in steel making. Mini Blast Furnaces with a capacity of over 3.5 million tons of hot metal per annum have been set up over the last decade with an investment of over Rs3000/- crores employing over 100,000 people.
- Low ash metallurgical coke having low sulfur and low phosphorus is the basic input for Mini Blast Furnace Industry. It constitutes above 60-70% of the cost of production of Steel/Pig Iron through blast furnace route. Mini Blast Furnace Industry requires annually in excess of 2.5 million tonnes of low ash metallurgical coke of desired chemistry. The desired quantity of metallurgical

coke required by the blast furnace industry being highly insignificant from indigenous sources, the mini blast furnace industry is totally dependent on imports of metallurgical coke.

- Min Blast Furnace Industry has never been a part of domestic coke producers' market and principal customer of domestic industry. In the meeting taken by the Steel Secretary on the 26th November, 1999 Indian Metallurgical Coke Manufacturers Association (IMCOM) explained that the blast furnace units were not the principal markets of the coke producers. It was also agreed by IMCOM that the exemption of the blast furnace units from anti dumping duty was vital for the survival of the mini blast furnace industry. IMCOM expressed that they had no objection if the government exempts the blast furnace industry from the purview of anti dumping duty. Considering these facts, the government while issuing the notification No. 69/2000-Cus dated 19.05.2000 excluded the Steel or Pig Iron Manufacturers using Blast Furnaces, from the purview of anti dumping duty on metallurgical coke of Chinese origin provided it follows the procedure set out in the Customs (Import of Goods at concessional rate of duty for manufacture of excisable goods) Rules, 1996. This facility was also extended to manufacturers of steel using COREX technology vide Notification No. 100/2002-Customs dated 01.10.2002.
- In the context of the facts prevailing at present concerning Low Ash Metcoke required by the Mini Blast Furnace Industry, imposition of anti dumping duty on Metcoke of Japanese origin is neither necessary nor desirable. It causes severe damage to Mini Blast Furnace Industry and at the same time does not provide any protection to the Domestic Industry. Mini Blast Furnace Industry and Steel Producing units under COREX technology should be excluded from the purview of Anti Dumping Duty. Mini Blast Furnace Industry requires Metcoke of a special variety and therefore, the specification of Metcoke have to be detailed while deciding the 'like article' as the quality of Metcoke depends on a number of parameters.

Indian Ferro Alloy Producers' Association:

While reiterating most of the arguments put forward by other interested parties as far as the product under consideration, capacity constraints of the domestic industry, captive consumption, post POI price structure etc. are concerned, the Association has made the following further submissions specific to the Ferro Alloy industry.

- That the specific low Ash and low Phos coke is not available domestically and the Ferro Alloy Producers have to depend on imports for the same.
- That the Indian Metcoke producers have earlier conceded that imports by Ferro Alloy Producers and Pig Iron producers do not cause them any injury and Govt. of India has earlier exempted the imports made by these users through two notification from the Antidumping Duty in the case of China. On account of this alone there is no causal links for the injury caused to the domestic industry.

- In any event, the Designated Authority has been recommending antidumping duty on variable basis (reference price basis) and such benchmark pricing should ensure that the Indian Consumers are not made to import the material at unreasonably higher prices.

D. EXAMINATION BY AUTHORITY

The foregoing submissions made by the exporters, importers and the petitioner, to the extent these are relevant as per Rules and have a bearing upon the case, have been examined, considered and dealt with at appropriate places in these findings.

1. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

The product, as described in the petition under investigation, is Metallurgical Coke (also referred to as Metcoke) with ash content less than 18%, originating in or exported from Japan.

Metcoke produced is produced by destructive distillation of Metallurgical (coking) coal in the absence of oxygen at high temperatures, (generally ranging around 1000 degrees centigrade) without burning the coal. It mainly contains carbon along with some mineral and residual volatile material. Metcoke is used as primary fuel in industries where a uniform and high temperature is required in kilns or furnaces.

Metcoke is classified under chapter 27 (under sub-heading 27.04) of the Customs Tariff Act, 1975. The subject Metcoke can be imported under OGL and attracts a basic customs duty of 15% (2002-2003). The classification, manufacturing process and usage of the product indicated herein are, however, indicative only and in no way binding on the scope of the product under consideration. Metcoke (including Subject Metcoke) is used in various industries including pig iron, foundries, ferro alloys, chemical, integrated steel plants and others.

The Authority notes the contentions of the petitioners that the subject Metcoke imported from Japan uses coal having ash content of less than 13%. In the process of coking, the volatile matter in the coal gets burnt or extracted and thus the ash content in the residual coke increases by same percentage as the volatile matter in the coal. Thus coal with 13% ash content and about 24-25% VM will generate coke with 18% ash content and Subject Metcoke of only up to 18% is being imported into India. Therefore, Metcoke with ash content less than 18% should be subjected to investigation in this case.

However, the Authority also notes that the coke imported from Japan contains only around 13% ash. The domestic producers and the petitioners in this case also manufacture coke with ash content less than 15% only. The domestic industry can plead for inclusion, within the product under consideration, what has actually been imported and caused injury. In this connection the Authority recalls the detailed examination and deliberation in the preliminary and final findings concerning antidumping investigation of Metcoke from China (vide

notification No. 8/2/97-ADD dated 27th August 1998. In the said findings the Authority, after taking into account all views expressed, and technical opinions on the use of low ash Metcoke and also the input-out norms of DGFT, concluded that ash content of 15% or less is the appropriate indicator for separating the low ash Metcoke from Metcoke produced from domestic coal, which contains higher percentage of ash. Therefore, the Authority does not find any reason as to why the present investigation should extend to Metcoke with ash content up to 18%. The reason extended by the domestic industry for covering Metcoke with less than 18% ash content does not appear to be based on any additional facts and reasons: Merely because Japanese producers use coal with ash content up to 13% does not prove that the coke exported from Japan will have ash content up to 18% and therefore, should be treated as the product under consideration.

Therefore, the authority holds that the product under consideration in the present investigation would cover low ash Metcoke with ash content less than 15%, originating in or exported from Japan (herein after referred to as subject Metcoke).

2. LIKE ARTICLE

Having decided to restrict the investigation to Low Ash Metcoke with ash content below 15%, the Authority proceeds to determine the 'Like Article' for the purpose of deciding the standing of the domestic industry and also for the purpose of determining the 'Normal value' in the exporting country.

Rule 2(d) of the Antidumping Rules define "Like Article" as an article which is identical or alike in all respect to the article under investigation for being dumped in India or in absence of such article, another article which although not alike in all respect, has characteristics closely resembling to those articles under investigation.

The Product under consideration in this case is Low Ash Metcoke with ash content below 15%. The domestic industry contends that they produce low ash Metcoke from imported coal (mainly from Australia). The Metcoke produced by other producers who are members of the ICA, either use domestic coal, which contain very high percentage of ash, or blend it with imported coal. The resultant coke is high in ash content (above 15%). The imported coke from the subject country contains less than 15% ash, and is technically and commercially substitutable for the domestic coke produced by the petitioners and therefore, is to be considered as the like product. The Authority also notes the claims of the petitioners that they can produce all types and grades of low ash Metcoke. The petitioners have also claimed that there is no difference between the Metcoke produced by the domestic industry and that exported from the subject country, which can have impact on price.

However, the exporters and importers and other interested parties contend that Low Ash Metcoke produced by the Indian industry and imported from the subject country are not comparable on many technical parameters like Moisture content, Volatile Matter (VM), Sulphur, Phos, M40 and M10 strength etc. Therefore, they are not truly technical and commercial substitutes. The technical

specifications of Metcoke required for various uses, particularly, sulphur and phosphorous content in it, vary. The domestic producers have not been able to produce the right kind of Metcoke (low Phos and low sulphur) and of right sizes for industries like, Ferro Alloys and Pig Iron Manufacturers. However, the petitioners claim that the consumers have used the Metcoke produced by them interchangeably and for blending with imported Metcoke.

The Authority notes that Metallurgical coke is manufactured by destructive distillation of coking coal in coke ovens and the quality of coke depends upon the coal, which is the only raw material in the process. The ash content, sulphur as well as phosphorous content in the coke depends upon the coal being used and content of these material in the coal. There is no other technology-related issue as far as the quality of coke is concerned except in some recovery plants where stamping devices are used for making blocks of coal for horizontal feeding into these ovens. This permits better coking of the coal and higher strength of the resultant product. The recovery plants collect the volatile matters in the coal, which varies depending upon the coal being used. The coke oven gas so collected is further processed for extraction of various by-products or can be simply used, after extraction of noxious substances, as fuel for heating the coke ovens, power generation etc. However, the ash contents, as well as other chemical, like sulfurs and Phosphorous, in the resultant coke depends upon the type of coal being used.

The Authority, in this connection, recalls detailed deliberation on the issue of 'like article' in the final findings in the matter of Metcoke from China vide Notification No. 8/2/97-ADD dated 27th August 1998. After a detailed deliberation in that case the Authority held that..."it is only the production of low ash content Metcoke which is "like article" to the imported Chinese coke. The contention of the exporters and importers that high ash content Metcoke should not be considered as like article has considerable force and is accepted in view of the facts and circumstances of the case."

"In addition to the above, the authority also observes that in the standard input-output norms of the Directorate General of Foreign Trade, where for production of pig iron (blast furnaces) one of the inputs shown is low ash content metcoke (with ash content below 15%). The Authority is therefore, inclined to agree with the exporters/importers that only metcoke with ash content of 15% and below, irrespective of its producer in India, is a "like article" to the imported Chinese coke. The Authority, therefore, concludes that metcoke with an ash content of 15% and below, irrespective of its producer in India is a "like article" to the imported Chinese coke".

Considering the manufacturing process of the metcoke and the issues settled earlier by the authority in a similar case, the authority holds that metcoke with an ash content of 15% and below, irrespective of its producer in India is a "like article" to the imported Japanese coke with similar ash content.

The Authority however, notes the arguments of Indian Mini Blast Furnaces and Indian Ferro alloys Industry that the coke required by these industries and

thus imported by them are different from the coke being manufactured by the domestic industry and therefore, should be exempted from the antidumping duty.

The ferro alloys industry has submitted that the coke required by them is of a different specification. They require coke only in the size range of 10-30 mm and with a phosphorus content not exceeding 0.0166%. The coke produced from Indian coal has a phosphorous content of above 0.15% and the Ferro alloys producers cannot at all use it. The coke produced by the petitioners from imported coal and other producers i.e. members of ICA Dhanbad from domestic coal is not suitable for Ferro alloys producers because of high ash and phosphorus content. Manufacture of Ferro alloys is a continuous process and as such the plant has to be operated continuously without any interruption and stoppage. The Ferro alloys industry requires low ash, low phosphorous, low sulphur metcoke having stringent specification which is not available from indigenous sources. Because of this, the industry has to import low phosphorus, low ash and low sulphur metcoke from different countries, including the subject country, as the indigenous metcoke can not be used for Ferro Alloy production..

Association of Indian Mini-Blast Furnaces has also made a similar plea for exemption from the antidumping duty on the grounds that size requirement for the mini-blast furnaces is different and the domestic industry is unable to cater to the volume demand of this sector. The demand constraint aspect has been dealt separately in this finding.

The short point under consideration for the purpose of determination of 'like article' is, whether the coke being exported from the subject country and imported by these users are technically and commercially substitutable for the coke being manufactured by the domestic industry and therefore, fall within the definition of 'like product'.

As far as the requirement of the Ferro Alloy Industry is concerned, the coke being imported by this industry is of low ash as well as low phosphorous and low sulphur content. These industries cannot use any coke, which does not match the stringent specification, particularly, of phosphorous content. It is the case of the Ferro Alloy Industry that low phos and low sulphur metcoke of desired specification is not being produced by the domestic industry and they have to import it, in spite of antidumping duty. They contend that almost 98% of their requirement is imported even when there is antidumping duty on Chinese Metcoke, simply because Indian producers do not produce this Metcoke. The Domestic Industry has argued that the coke used by the Ferro Alloy Industry can be produce by them as the quality of coke and the ash, as well as phosphorous and sulphur content in it is directly related to the quality of coal being used and no other technological issue is involved in it.

The Authority notes that though it is technically possible for the domestic industry to produce the coke of the grade required by the Ferro Alloys Industry, it has not produced any substantial quantity of metcoke of this grade and import data shows that most of these metcoke has been imported in the past, even when antidumping duties were in force. The fact also remains that the grade of metcoke imported by these users can not be substituted by the metcoke being produced by the domestic producers, in any significant manner. Authority also notes that total

metcoke (of low ash and low phos) requirement of this segment is very low and it may not be commercially viable for the domestic producers to import coal of specific grade to manufacture metcoke of this grade.

Attention of the Authority was also drawn by various interested parties to the deliberation in the previous case involving import of Metcoke from China. The issue of specific requirements of certain users was deliberated in the previous case and the authority noted that: "some user Industry groups like manufacturers of ductile iron pipes, Ferro alloys have indicated that the metcoke required by them has to have some other physical as well as chemical properties. For instance, it has been indicated by the ductile iron pipes Industry that the phosphorus content in the metcoke required by them should be less than 0.035%. While it is appreciated that certain Industries may have special requirements, anti-dumping rules do not permit analysis on the basis of specific end users when there is a high degree of substitution possible among different types of user industries. The Authority therefore, is not in a position to make any separate categorization for users with special requirements".

In this connection the Authority notes that the arguments in the previous case was for an end-use based exemption for specific industries and Authority had rightly held that it had no authority under the Rules to provide for end use based exemption. However, the argument of the Ferro Alloy Industries on the Like Product issue has considerable force and therefore, the Authority is inclined to accept the argument of these parties that the product used by them is not technically and commercially substitutable by the product manufactured by the domestic industry and therefore, should be excluded from the scope of the investigation.

Therefore, the Authority holds that the metcoke containing low ash (up to 15%) and low phos (up to 0.035%) and low sulphur (up to 0.5%) mainly used by the Ferro Alloys Industries and imported from the subject country is not a technically and commercially substitutable product for the domestically produced metcoke and should not be treated as 'like product' within the meaning of the term as defined under the Rules.

End-Use Based Exemption

As far as the Indian Mini Blast Furnaces are concerned, their entire argument is based on end use based exemption on the grounds that because of the demand supply gap the domestic industry is unable to supply the quantity and quality required by this segment and therefore, these importers should not be treated as causing injury to the domestic industry. In this connection they have quoted the minutes of an agreement reached by the Domestic industry and the Mini Blast Furnaces to exclude these segment from Antidumping Duty. The users have argued that on the basis of this agreement and to promote the Indian Mini Blast Furnaces, Govt. had, in the earlier case, exempted this sector from the antidumping duty on actual user basis, vide notification No. 69/2000 Dated 19.5.2000 under Section 25(1) of the Customs Act. However, the domestic industry has argued that it may have been prudent in the national interest at relevant time to exempt blast furnaces and ferro alloy users when there was a

capacity constraint initially. But there can be no doubt that this exemption has contributed to the injury being faced by the domestic industry today. It has resulted in slowing down the process of capacity addition. Now that the domestic industry has added significant capacity and setting up of new coke plants are in the pipeline there is no case to exempt any segment on the grounds of capacity constraints. The petitioners have also argued that the Authority does not have the powers to exempt certain classes of users while recommending Antidumping duty, as Rule 19 of the Antidumping Rules state that any duty imposed under Rule 13 or 18 shall be on a non-discriminatory basis and applicable to all imports of such article, from whatever sources found dumped and where applicable, causing injury to domestic industry except in the case of imports from those sources from which undertaking in terms of Rule 15 has been accepted.

The authority notes that the Mini Blast Furnaces require low ash Met Coke (with ash content less than 15%) of sizes between 20-50mm. The coke manufactured by the domestic industry does match these specifications and therefore, is both commercially and technically substitutable with the subject Metcoke being imported from the subject country. The Authority also notes that the exemption from Antidumping duty granted to a section of the industry in the earlier case by the department of Revenue, within sovereign jurisdiction of the Government of India, under relevant provisions of the Customs Act, has no bearing on the instant case.

The Authority, therefore, for the purpose of preliminary determination, pending final determination, holds that the subject goods produced by the domestic industry and those exported from the subject country except for the low ash, low phos coke used by the ferro alloy industry as stated above, are like article within the meaning of the Rule 2(d).

3. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

The petition has been filed by Indian Metallurgical Coke Manufacturer's Association (IMCOMA), on behalf of the domestic industry. Six domestic producers are party to the petition and M/s Gujarat NRE Coke Ltd has supported the petition. These units manufacture Low Ash Metcoke with Ash content below 15% and combined output of these units (during the POI) was *****MT.

In addition to this, there are other manufacturers of Metcoke (Members of ICA) who manufacture coke with higher ash content and therefore do not qualify to be included in the domestic industry within the meaning of producers of 'like article'. There are also other producers i.e. integrated steel plants who produce metcoke of various ash content depending upon their own requirement for captive consumption. In this connection the Authority notes that the definition of the "domestic industry under Rule 2(b) reads as follows:

"Domestic Industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major, proportion of the total domestic production of that article, except when such producers are related to exporters or importers of the alleged dumped articles or are themselves

importers thereof, in which case such producers shall be deemed not to form part of domestic industry”.

“Provided that in exceptional circumstances referred to in sub Rule (3) of Rule 11, the domestic industry in relation to the article in question shall be deemed to comprise two or more competitive markets and the producers within each such market a separate industry if;

- (i) the producers within such a market sell all or almost all of their production of the article in question in that market; and
- (ii) the demand in the market is not in any substantial degree supplied by producers of the said article located elsewhere in the territory.”

The coke produced by these ISPs or captive producers are basically captive raw material production of these units and do not enter the commerce of the domestic market and therefore, does not constitute a part of the domestic industry within the meaning of sub rule 3 (i) and (ii) above. Their production at best constitute a separate market within the meaning of the Rules quoted above and has to be kept outside the purview of the domestic industry for the subject product. Moreover, some of these units also import the subject metcoke for supplementing their consumption.

The Designated Authority and the Hon'ble CEGAT have held in earlier cases that captive producers, who consume their entire production, are not to be considered as a part of the domestic industry. Accordingly the production and capacity of these producers have not been taken into account for determining the standing of the domestic industry.

Therefore the Authority concludes that the petitioners constitute major proportion of the domestic production of the subject metcoke and have the standing to file this petition under relevant Rules.

4. Period of Investigation

The Period of Investigation (POI) in this case was fixed for 15 months beginning 1st April 2001 to 30th June 2002. The exporters, importers and other interested parties have argued that an old/ stale POI has been accepted by the Authority to investigate the case. In this connection the Authority notes that the petition in this case was filed in September 2002 with the data up to 31st March 2002. It was on the insistence of the Authority to update the data set with more recent data, the petitioners submitted data up to 30th June 2002, as complete data was available up to that period only. The Authority notes that there is no specific provision in the Agreement or in the Antidumping Rules to suggest a specific POI. However, Note of WTO Agreement (Art 2.2.1) suggests that the period of investigation should not be less than 6 months. As such there is no prescription or restriction with reference to the period of investigation in the respective provisions of Antidumping Law. However, the relevant guidelines for fixing the period of investigation (POI), adopted by the Authority provide that the period taken into consideration for detailed investigation into dumping and injury should be as

representative and as recent as possible. The most desirable period of investigation is a financial year, provided there is reasonable proximity between the end of the financial year and the filing of the application. The Authority therefore, holds that on the date of submission of the petition most recent data set available was up to 30th June and accordingly the POI was correctly fixed. Therefore, there is no need for altering the POI and admission of post POI data for the current investigation.

5. NORMAL VALUE & EXPORT PRICE

In terms of Section 9A(1)(c), of the Antidumping Rules normal value in relation to an article means:

- (i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
- (ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:-
 - (a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
 - (b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section(6);

In terms of the above provisions the normal value and ex-factory export price determination is illustrated below.

NORMAL VALUE

a. M/s JFE Steel Corporation Japan

The Authority notes that M/S JFE Steel Corporation (JFE) is the producer and exporter of the subject Metcoke from Japan and also exports the products through M/s Mitsubishi Corporation and other Trading Companies. JFE is an Integrated Steel Producer (ISP) and produces Low Ash Metcoke for its own consumption out of imported coal from Australia and other countries. The coke being released for merchant trading, either in the domestic market or for export sales, are the steel plant rejects i.e. of particular sizes, which can not be used in their own blast furnaces. JFE employs recovery type coke ovens for producing low ash metcoke and the recovered coke oven gas is used in steel making and for other commercial uses. The producers have provided details on the installed capacity and cost of production of the subject goods during the Period of Investigation.

JFE has provided the details of quantity and value of sale of subject goods in the home market during the Period of Investigation. The producer has also indicated that their records are in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles and has claimed that the normal value be determined on the basis of their domestic selling price. In this respect the rule position (Sub-rule 2, Annexure 1) is as follows:

“Sale of the like product in the domestic market of the exporting country or sales to a third country at prices below per unit (fixed and variable) costs of production plus administrative, selling and general costs may be treated as not being in the ordinary course of trade by reason of price.”

The Authority has examined the cost of manufacturing of the subject goods, Selling and general administrative expenses (SGA) and the recoverable cost of the by-products generated in the recovery type coke oven of the producer. However, Authority notes that the producer has allocated a very low proportion of their total SGA expenses to the Metcoke exports compared to the total turnover. The Recovery cost indicated by the producers for their recovery type coke ovens are much on the higher side compared to similar coke ovens of integrated steel plants in India. Therefore, for the purpose of preliminary determination pending verification and final determination, the authority has appropriately normated SGA expenses of the producers on the basis of turn over ratio. The recovery cost has also been normated on the basis of efficient ISP in India. In this connection the Authority recalls its own decision in the case of Metcoke from China, where the Recovery factor of SAIL was taken as the basis for allowing cost recovery for the foreign producers. Therefore, for the purpose of preliminary findings the authority proceeds to adopt the same factor of recovery to work out the cost of manufacturing in this case also, pending final verification and determination. The Authority also notes the contention of the petitioners that the cost recovery of by products from a recovery type coke oven is largely offset by the capital cost of setting of a recovery plant and downstream facilities. However, pending verification and final determination, the Authority adopts the recovery factor as 19.44% as fixed earlier and proceeds to calculate the cost of manufacturing and SGA as follows:

Manufacturing Expenses:		(Japanese YEN per MT)	
Raw Materials	Coal @ **/ MT of Coke	*****	
	Others : @***%	*****	
Consumables and Stores		*****	
Utilities		*****	
Direct labour		*****	
Manufacturing Overheads		*****	
Depreciation		*****	

	Total	*****	
By Product Recovered @ 19.44%	(-)	*****	
SGA Expenses on Turn over basis		*****	

	Total Cost to make and sell	*****	

This average cost to make and sell has been compared with the domestic selling prices and most of the transactions were found to be below the average cost to make and sell. Therefore, for the purpose of preliminary determination pending verification and final determination, the Authority disregards the domestic sale data and proceeds to work out the normal value on the basis of the cost of manufacturing and a reasonable profit margin of **%. Accordingly, the normal value is worked as JYEN***** i.e. US\$ ***** Per MT @ the exchange rate of JYEN *****=US\$1.00.

EXPORT PRICE

The Authority notes and the producer M/s JFE Corporation has indicated that the subject goods manufactured by them have been exported to India through different traders like Mitsubishi Corporation and Daichu etc. The producer has provided the data on their sale invoices to these trading companies who have exported these goods on back to back basis to the Indian importers. On the basis of these invoice values the average net export price is worked out as US\$***** PMT on Dry basis. Since the export price indicated have been claimed to be at the ex-works level, no adjustments for packing, inland freight, insurance, storage, handling, sales charges, overseas freight, overseas insurance, clearance and handling and port charges have been necessitated, pending verification and final determination. The Authority, for the purpose of preliminary determination, has considered the net ex-works export price as claimed by the exporter/ producer on dry basis as US\$*****/PMT.

b. M/s Mitsubishi Corporation, Japan

Normal Value

M/s Mitsubishi Corporation, Japan has submitted that it is only a Trading Company and has no manufacturing facility for the subject goods. They have, however, referred to the cost data of M/s JFE steel who is the primary producer of the subject goods, which are traded by them for exports to India. Therefore, the Authority proceeds to work out the normal value for this exporter based on the cost of manufacturing and selling by the primary producer and the domestic selling price of this exporter.

Cost of manufacturing plus SGA of the producer plus a reasonable profit (@**%) for the manufacturer on its sell to the unrelated trader works out to JYEN*****/PMT. This has been compared to the Domestic selling price of the Exporter in Japan. Since the Domestic selling price of the subject goods by the Exporter in Japan are below the Cost of manufacturing plus SGA of the producer, the Authority proceeds to disregard these selling prices and construct the normal value after adding a reasonable profit margin for the trader @**% to the above. The normal value for this exporter therefore, works out to be JYEN *****/PMT i.e. US\$*****/PMT at the exchange rate of JYEN124.1698=US\$1.00.

Export Price

The exporter has produced the export data on the basis of which net export price has been worked out as US\$***/PMT, net of packing, inland freight, insurance, storage, handling, sales charges, overseas freight, overseas insurance, clearance and handling and port charges etc.

c. All other Exporters/Producers in Japan

Normal value

No other exporter/producer except the above have responded to the questionnaires and the Authority notes that there is only one stand alone producer of Metcoke in Japan, other than the integrated steel plants, who exports almost all its production to the North America. Therefore, for the purpose of Preliminary determination, the Authority has worked out the normal value of the non-cooperative exporters from Japan by adding a commission amount @**% to the normal value of M/s Mitsubishi Corporation. Accordingly the normal value for all non-cooperative exporters from Japan work out as US\$****/PMT, for the purpose of preliminary determination.

Export Price

Since other exporters from Japan have not provided any data on the normal value and export prices, the Authority proceeds to determine the lowest export price from the data produced by the importers and works out the export price as US\$***/PMT.

DUMPING MARGIN-Comparison of Normal Value & Export Price

The rules relating to comparison provides as follows:

"While arriving at margin of dumping, the Designated Authority shall make a fair comparison between the export price and the normal value. The comparison shall be made at the same level of trade, normally at ex-works level, and in respect of sales made at as nearly possible the same time. Due allowance shall be made in each case, on its merits, for differences which affect price comparability, including differences in conditions and terms of sale, taxation, levels of trade, quantities, physical characteristics, and any other differences which are demonstrated to affect price comparability."

The authority has carried out weighted average normal value comparison with the weighted average ex-factory export price in Period of Investigation, for evaluation of the dumping margin for all the exporter/producers of the subject country.

The dumping margin for exporter/producers comes as under:

Exporter	Normal value(NV) \$/MT	Export Price(EP) \$/MT	Dumping Margin	Dumping margin as % of CIF Value
1. M/s JFE Steel Corporation, Japan	*****	*****	*****	39.63%
2. M/s Mitsubishi Corporation Japan	*****	*****	*****	39.89%
3. All other exporters/producers in Japan	*****	*****	*****	53.56%

6. INJURY AND CAUSAL LINK

Under Rule 11 supra, Annexure-II, when a finding of injury is arrived at, such finding shall involve determination of the injury to the domestic industry, ".....taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...." In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, such indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilisation, sales quantum, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. are to be considered in accordance with Annexure II (iv) of the rules supra.

As regards the threat of injury, the Authority notes that the Anti-Dumping Rules states as follows:

"A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. The change in circumstances, which would create a situation in which the dumping would cause injury, must be clearly foreseen and imminent. In making a determination regarding the existence of a threat of material injury, the DA shall consider, inter-alia, such factors and;

- a significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation;
- sufficient freely disposable or an imminent, substantial increase in capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially

increased dumped exports to Indian market, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;

- c) whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and,
- d) Inventories of the article being investigated.

Keeping in view the above position the Authority notes and observes the following economic parameters in the case of domestic producers-

1. Capacity and Domestic sale:

The domestic Industry has increased its capacity from about 5.00 lakh tonnes to about 11 lakh tonnes i.e. an increase of about 220% between 1999-and 2002. However, this increase in capacity is mainly due to the process of recovery of the industry after imposition of antidumping duty on dumped import from China, which was injuring the industry. However, the Capacity utilization during the same period remained between **** to ****%, marginally increasing during 2001-2002. Total demand went up by approximately 16%, from *****MT to *****MT during the same period and the share of the domestic industry also went up from about 13% to 26%. However, though the domestic capacity is about 37% of total demand, its market share remained below 26%.

2. Increased Imports from the Subject Country:

The share of imports from the subject country in comparison to the total imports has increased substantially from ***% in 2000-2001 to ***% during the period of investigation. And during the same period the market share of the imports from this country has also increased from ***% to ***%. The increased import and market share coincides with the drop in the export price of the subject goods from the subject country, which fell from Rs4303/- PMT to Rs4188/- PMT during the identical periods.

3. Price Undercutting and Under selling:

The imports from the subject countries have entered the Indian market at a price, which is below its normal value and the non-injurious price of the domestic industry at which the domestic price can produce and sell the subject goods and earn a reasonable return on its investment. Unit price realisation compared to the 1999-2000 price of the domestic industry fell to 95.5% during the POI. Average Non Injurious price of the domestic industry has been worked out to Rs*****PMT, whereas the average selling price of the domestic industry was Rs****/PMT during the POI, leading to price under selling to the extent of **%. The average landed value of the imported subject goods was Rs*****PMT during POI resulting in price undercutting of about ***%. Thus the Net Sales Realization in the POI has been below the Non-Injurious Price, leading to financial losses.

4. Profitability

Total sale value of the subject goods increased by 213% compared to the same in 1999-2000, but the cost to make and sale also increased by 302% during the same period. This indicates that the domestic industry was selling at unremunerative level in order to remain in business and the investment was unprofitable at this level of prices.

5. Return on investment and cash flow

The return on investment by the domestic industry has been negative during the POI and there has been a considerable impact on the cash flow.

6. Net Sales Realisation

The Net Sales Realisation has been Rs**** PMT in 1999-00 which fell to Rs**** PMT in 2000-01 and marginally increased to Rs. **** PMT during the POI

7. Demand and potential for growth for domestic industry

The demand of the subject goods has increased by about 16% from 1999-2000 to 2001-2002. Therefore, demand has not been a factor for causing injury to the Domestic Industry. But negative return on investment for a considerable period due to dumped imports from the subject country has scuttled the growth of the domestic industry, though there is a tremendous scope for growth as has been seen from the growth during the last three years, when protection of antidumping was available against dumped imports from China.

8. Inventory of domestic industry

The domestic industry has improved its inventory position during the period of investigation and therefore, it is not a factor for causing injury to the industry.

9. Employment and Wages

Due to increase in capacity there has been increase in employment. Wages have not been affected by the market condition due to the Labour Laws. These factors can not therefore, be considered to be contributing to the injury of the domestic industry.

10. Magnitude of Dumping and injury

The dumping margin, calculated as a % of the export price, is significantly high for all the exporters from the subject country. The margin of injury has also been calculated as the difference between provisional non-injurious price for the domestic industry, worked out on the basis of cost data of the domestic producers as follows:

3059 G1/03 - 11

a) JFE Steel Corporation:

NIP:	Rs	*****	US\$*****
(Exch. Rate ****)			
Landed value of Imports:			US\$*****
Injury Margin:			US\$*****
Injury Margin as % of CIF			24.55%

b) Mitsubishi Corporation

NIP:	Rs*****	US\$*****
Landed value of Imports:		US\$*****
Injury Margin:		US\$*****
Injury Margin as % of CIF		18.25%

c) Others

NIP:	RS*****	US\$*****
Landed value of Imports:		US\$*****
Injury Margin:		US\$*****
Injury Margin as % of CIF		28.57%

11. Capacity of the exporters

The Authority also notes that the capacity of the exporter M/s JFE Steel Corporation is very significant compared to the available demand in that country and total market demand in India. Therefore, the quantity of the subject goods being dumped from the subject country, leading to price suppression, is an imminent threat of injury to the Domestic Industry. The domestic producers in view of such dumped prices will not be able to retain their domestic selling price above a reasonable level which otherwise would accrue to them if there was no such dumping.

The Authority also notes that the exporter i.e. M/s JFE Steel Corporation imports Metcoke of appropriate quality from China for its own consumption and its own surplus from its coke ovens, which it can not consume in its own blast furnaces, are being exported to India at dumped prices. The authority notes that generation of different sizes of Metcoke in the coke ovens is a normal phenomenon and by supplementing its own requirement through imports from China, the exporter is in a position to continue to dump the subject goods in the Indian market. Therefore, keeping in view the present available capacity and the price undercutting by the recent dumped imports, the Authority provisionally holds that the exports from Japan are materially injuring and threat to cause material injury to the domestic producers of the subject goods in India.

Causal Links

After examining all the factors as laid down and discussed above, the Authority provisionally holds that the dumped import from the subject country has caused material injury to the domestic industry and no other factor can be attributed to the injury suffered by the domestic industry. The domestic industry also faces threat of

material injury due to continued dumped imports from the subject countries as the exporter in the subject country has sufficient capacity to continue dumping. The potential growth and establishment of the domestic industry has also been affected by the dumped imports.

7. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

The Authority holds that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.

The Authority also recognizes that though the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products, however, fair competition in the Indian market will not be reduced by these anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by the dumping practices and would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice of the subject goods to the consumers. Imposition of anti-dumping measures would also not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

8. LANDED VALUE

The landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the customs under Customs Tariff Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

D. CONCLUSIONS:

The Authority, after examining the issues involved, and arguments of all the interested parties provisionally holds that:

- a) The subject goods in all forms originating in or exported from the subject country have been exported to India below its normal value.
- b) The domestic industry has also suffered material injury by way of financial losses due to depressed Net Sales Realization (NSR) on account of price depression caused by low landed prices of the dumped subject goods.
- c) The injury has been caused to the domestic industry by dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries.
- d) The Authority recommends provisional anti-dumping duty on imports of subject goods falling under Chapter 27 originating in or exported from the subject country.
- e) It was considered to recommend the amount of anti-dumping duty equal to the margin of injury so as to remove the injury to the domestic industry accrued on account of dumping. Accordingly, it is recommended that provisional anti dumping duties equal to the difference between the amount

indicated in the column 9 of the table annexed to this notification, and the landed value of subject goods, in US\$/PMT, be imposed, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, on all imports of subject goods originating in or exported from subject country under Chapter 27 of Customs, sub-heading 270400, pending final determination.

E. FURTHER PROCEDURE

The following procedure would be followed subsequent to notifying the preliminary findings:

- a. The Authority invites comments on these findings from all interested parties and the same would be considered in the final findings;
- b. Exporters, Importers, Petitioner and other interested parties known to be concerned are being addressed separately by the Authority, who may make known their views, within forty days from the date of the despatch of the letter. Any other interested party may also make known its views within forty days from the date of publication of these findings;
- c. The Authority would conduct verifications to the extent deemed necessary;
- d. The Authority would provide opportunity to all interested parties for oral submissions, for which the date and time shall be communicated to all known interested parties separately;
- e. The Authority would disclose essential facts before announcing final findings.

L.V. SAPTHARISHI, Designated Authority

(L. V. SAPTHARISHI), Designated Authority

ANNEXURE - I

S.No	Sub Heading or Tariff Item	Description of Goods	Speci fication	Country of origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount	Unit of Measure ment	Curr ency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	270400	Low Ash Metallurgical Coke with Ash content less than 15% (other than that containing Phosphorous less than 0.0166% required for Ferro Alloy Production)	Nil	Japan	Any country	Any Producer	Any Exporter	118.44	MT	US\$
2	270400	Low Ash Metallurgical Coke with Ash content less than 15% (other than that containing Phosphorous less than 0.0166% required for Ferro Alloy Production)	Nil	Any Country	Japan	Any Producer	Any Exporter	118.44	MT	US\$